ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष- 6, 2083 | dopaharmetro | epaper.dopaharmetro.com | dopaharmetro | वर्ष-09, अंक - 345 | पेज 8, मूल्य 2 रुपए

डाक पंजीयन क्रमांक: म.प्र./4-474/2024-26

भोपाल

20 जून 2026 शनिवार

बेबाक खबर हर दोपहर

दोपहर मेट्रो

आज का मौसम

37.3 अधिकतम

24.6 न्यूनतम

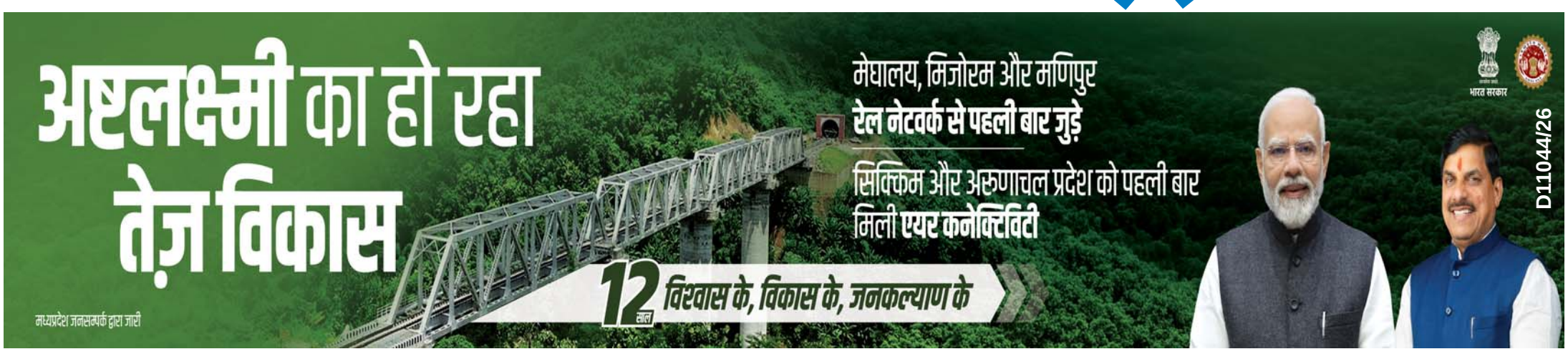

राम मंदिर चढ़ावा चोरी... ट्रस्ट से हटाए जा सकते हैं चंपत राय और अनिल मिश्रा

एसआईटी जांच में अब तक 150 संदिग्ध सामने आए, सख्त एक्शन की तैयारी

आज लखनऊ लौटेगी जांच टीम, सोमवार को सौंपी जाएगी रिपोर्ट

लखनऊ / नई दिल्ली. एजेंसी

अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी कर आस्था के साथ विश्वासघात को लेकर राज्य सरकार की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) की जांच में 150 संदिग्धों के नाम सामने आए हैं। इनमें से 25 लोगों पर कार्रवाई के आसार हैं। जिन लोगों से पूछताछ हो चुकी है, उन्हें अगले आदेश तक कहीं बाहर न जाने की चेतावनी दी गई है। अपनी जांच के छठवें दिन आज एसआईटी की टीम मंदिर पहुंच गई है। बताया गया है कि जांच पूरी कर टीम आज ही लखनऊ लौटेगी। सोमवार को सीएम योगी को जांच रिपोर्ट सौंपी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक, ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्रा पर कार्रवाई लगभग तय मानी जा रही है। दोनों को पद से हटाया जा सकता है।

इसके अलावा, मंदिर के निर्माण प्रभारी गोपाल राव को भी पद से हटाया जा सकता है। शुक्रवार को जांच टीम ने ने मंदिर परिसर में करीब 6 घंटे तक जांच की। टीम ने चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव से अलग-अलग पूछताछ की। साथ ही स्टेट बैंक के मैनेजर और कैशियर से भी सवाल किए गए। गोपाल राव के भतीजे और राम मंदिर कर्मचारी सोमेश आनंद से भी पूछताछ की जानी थी, लेकिन वे नहीं मिले। सूत्रों के अनुसार, उनका फोन लगातार स्विच ऑफ मोड़ में रहा।

सपा सरकार में मंत्री रह चुके पवन पांडेय ने 7 जून को दावा किया था कि राम मंदिर से 5 से साढ़े 7 करोड़ रुपए तक की चोरी की गई। अखिलेश यादव ने भी कहा था कि मामले पर सरकार की चुप्पी संदिग्ध है। चंपत राय ने सफाई दी थी कि अभी तक ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आई है। विवाद बढ़ा तो भाजपा नेता डॉ. रजनीश सिंह ने 9 जून को प्रधानमंत्री को लेटर लिखकर सीबीआई जांच की मांग की। 10 जून को प्रधानमंत्री कार्यालय ने मंदिर ट्रस्ट से मामले की रिपोर्ट मांग ली थी।

अब तक 2 करोड़ की बरामदगी

चढ़ावा चोरी मामले में पांच लोगों लवकुश, अवनीश, अनुकल्प, करुणे और रामशंकर उर्फ टिन्नू की निशानदेही पर अब तक 2 करोड़ रुपए की रिकवरी की गई है। ये सभी मंदिर में दान राशि की गिनती की ड्यूटी से जुड़े थे। मंदिर ट्रस्ट के कर्मचारी टिन्नू के घर से 13 जून को सोना मिला था। हालांकि, सोना कितना है, यह अभी स्पष्ट नहीं है।

जेवर दिए लेकिन नहीं मिली रसीद

जांच टीम ऐसे दानदाताओं से संपर्क की कोशिश कर रही है, जिन्होंने मंदिर ट्रस्ट के किसी कर्मचारी को जेवर सौंपे थे। रिपोर्ट में ये बिंदु शामिल किये जाएंगे कि कब और किसके हाथों में जेवर सौंपे गए। कोई रसीद दी गई थी या नहीं। मुंबई के एक कारोबारी अनिल विश्वकर्मा के बयान दर्ज किए गए हैं जिनका आरोप है कि उन्होंने रामलला के लिए 3 किलो चांदी का हार और 1 किलो चांदी की चरण पादुका टिन्नू यादव को सौंपी थी, लेकिन मंदिर की तरफ से कोई रसीद नहीं मिली। इसी तरह 60 किलो चांदी की ईंट दान करने वाले 'इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन' के नॉर्थ इंडिया हेड अनुराग रस्तोगी का कहना है कि उनकी चांदी का भी अब तक कुछ पता नहीं चला।

इजराइल-हिजबुल्लाह में टकराव रुका

अब आगे बढ़ेगी शांति की बात जिनेवा रवाना हुए अमेरिकी दूत

तेहरान/वॉशिंगटन डीसी

अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते के बाद आगे की शर्तों पर बातचीत के लिए विशेष दूत स्टीव विटकॉफ शनिवार को स्विट्जरलैंड रवाना हो गए हैं।

सीएनएन के मुताबिक, वॉशिंगटन और तेहरान फिर से बातचीत शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, जो पहले इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष के कारण टल गई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि हाल ही में सीजफायर के बाद माहौल कुछ हद तक शांत होने पर बातचीत फिर से आगे बढ़ सकती है। इस प्रक्रिया में डोनाल्ड ट्रम्प के दामाद जेरेड कुशनर के भी शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। इजराइल के हिज्बुला पर हमले के कारण शुक्रवार को होने वाली वार्ता टल गई थी। सूत्रों का कहना है कि इसके बाद अमेरिका, कतर और अन्य अंतरराष्ट्रीय शक्तियों की मध्यस्थता और बढ़ते दबाव के कारण आखिरकार इजरायल और हिज्बुल्लाह के बीच युद्धविराम हो गया है। अब जिनेवा वार्ता में अमेरिका और ईरान अंतिम डील तक पहुंचने के लिए 60 दिनों की समय-सीमा पर बात करेंगे। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची भी आज स्विट्जरलैंड पहुंच सकते हैं।

नीट परीक्षा : नागपुर के स्टूडेंट को मिला अबू धाबी का एग्जाम सेंटर

नागपुर। देशभर में कल एक शिफ्ट में नीट यूजी री एग्जाम आयोजित कराई जाएगी। अब नागपुर से एडमिट कार्ड में हुई गलती का एक मामला सामने आया है। दरअसल नागपुर के एक छात्र के नीट यूजी परीक्षा के एडमिट कार्ड में अबू धाबी में स्थित परीक्षा केंद्र का नाम उल्लेख है। छात्र का नाम अब्दुल्ला मोहम्मद तालिब है। एडमिट कार्ड में हुई गलती के बारे में पता चलने के बाद एनटीए ने अपनी गलती को स्वीकार किया और कहा यह समस्या तकनीकी खराबी के कारण हुई है।

न्यूज विंडो

टीएमसी नेता जहांगीर खान की पत्नी सरीना गिरफ्तार

कोलकाता। पश्चिम बंगाल पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस नेता जहांगीर खान की पत्नी सरीना बीबी को आज सुबह गिरफ्तार किया है। उन पर भीड़ जुटाकर पुलिस और केंद्रीय बलों पर हमले और जहांगीर खान को पुलिस हिरासत से छुड़ाने की कोशिश का आरोप है। पुलिस के मुताबिक, 16 जून को सरीना बीबी ने समर्थकों को जुटाकर थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन कराया था। भीड़ ने सुरक्षाबलों पर पत्थरबाजी भी की। मामले में अब तक 27 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जहांगीर खान को पुलिस ने 8 जून को भारत से भागने के दौरान नेपाल बॉर्डर के पास से गिरफ्तार किया था।

इंजन खराब हुआ, चार घंटे से ज्यादा खड़ी रही वंदे भारत

शिवसागर। वाराणसी से रांची जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस रात तकनीकी खराबी के कारण शिवसागर रोड स्टेशन के समीप चार घंटे से अधिक समय तक खड़ी रही। ट्रेन के इंजन में आई खराबी के चलते यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। शिवसागर रोड स्टेशन के पास पहुंची थी। इसी दौरान इंजन में तकनीकी खराबी आ गई, जिससे ट्रेन को रोकना पड़ा। रेलवे अधिकारियों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से दूसरा इंजन मंगवाया गया।

आज का कार्टून

आईएसआई ने रची थी आरएसएस कार्यालय पर हमले की साजिश

रांची, एजेंसी

पिछले दिनों झारखंड में आरएसएस दफ्तर पर हुए हमले की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के कथित 'ऑपरेशन यूपी' और 'ऑपरेशन पंजाब' की बात सामने आई है। पूछताछ में आरोपी अमन अंसारी ने बताया कि दुबई से भारत लौटने के बाद उसे पंजाब भेजा गया था। वहां उसे एक 'बॉस' से मिलना था। कुछ दिन पंजाब में रुकने के बाद वह वापस रांची लौट आया। इसके बाद आईएसआई हैंडलरों की ओर से उसे और उसके साथी सैफ को लखनऊ जाने का ऑर्डर मिला था। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक, लखनऊ में होने वाली इस बैठक का मकसद बेहद महत्वपूर्ण हो सकता था। पूछताछ में यह बात सामने आई है कि वहां आरोपियों को कोई बड़ा टास्क सौंपा जाना था। इसी वजह से एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि आखिर 'ऑपरेशन यूपी' का वास्तविक उद्देश्य क्या था। जांचकर्ता इस एंगल से भी जांच कर रहे हैं कि कहीं लखनऊ के बाद अयोध्या जाने की कोई योजना तो नहीं थी।

कांग्रेस विधायक के कार्यालय पर फायरिंग

रोहतक। रोहतक के महम से कांग्रेस विधायक बलराम दांगी के कार्यालय पर देर रात अज्ञात लोगों ने चार गोलियां चला दी। दो गोली कार्यालय के मुख्य दरवाजे के शीशे के आर-पार हो गई, जबकि दो एल्युमिनियम के दरवाजे में धंस गई। महम पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है। साथ ही विधायक बलराम दांगी से कार्यालय में पहुंचकर जांच पड़ताल की। प्रदेश में सियासी तौर पर महम हलका अहम रहा है। हलके को न केवल 1990 के महम कांड से जाना जाता है, बल्कि ताऊ देवीलाल भी 80 के दशक में हलके से विधायक बनकर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। खुद आनंद सिंह दांगी कई बार विधायक बने थे।

73.5 करोड़ में निपटा दिया 1,537 करोड़ का कर्ज

बैंकों की मिलीभगत से जनता के पैसे हड़पने की जांच हो - सुप्रीम कोर्ट

नईदिल्ली, एजेंसी

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने फंसे हुए कर्ज को असाइन और सेटल किए जाने की प्रक्रिया पर चिंता जताई है। उन्होंने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों, कर्ज लेने वालों और बैंकों के बीच कथित मिलीभगत से जनता के हजारों करोड़ रुपये की हेराफेरी के मामले में कहा कि यह इन सभी बीच मिलीभगत है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के गृह और वित्त मंत्रालयों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस से जवाब मांगा है। यह मामला नोएडा की एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी से जुड़े घोटाले से संबंधित है।

लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के अनुसार, चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस वी मोहन की वेकेशन बेंच ने इस मामले की सुनवाई की और केंद्र सरकार, आरबीआई, ईडी, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, सीबीआई और सेबी से चार हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता का कहना था कि पब्लिक सेक्टर के बैंकों का 1,537 करोड़ रुपये का कर्ज दो एआरसी के जरिए सिर्फ 73.5 करोड़ रुपये में निपटा दिया गया, जिससे जनता के पैसे का भारी नुकसान हुआ। इस परचीफ जस्टिस ने कहा, 'लेकिन यह कैसी व्यावसायिक समझदारी है कि आप जनता का पैसा इकट्ठा करते हैं और फिर उसे बिना सोचे-समझे कर्ज के तौर पर बांट देते हैं। और बाद में उसे वसूलने की कोई कोशिश नहीं करते? इस तरह का व्यवहार स्वीकार्य नहीं है।' आरोप है कि हजारों करोड़ रुपये के लोन भारी छूट पर ट्रांसफर किए जा रहे थे, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हो रहा था। इन आरोपों की जांच की भी मांग की गई है कि नोएडा की कंपनी जेकेएम ने बैंक से लिए गए लोन की 902 करोड़ से ज्यादा की रकम को दूसरी जगह इस्तेमाल किया।

दलबदल नहीं, अर्थबदल अपराध है... लोकतंत्र में दिल बदलने की सजा क्यों?

प्रसंगवश
राजेश सिरोठिया

भारतीय राजनीति में कुछ शब्द ऐसे हैं जिन्हें सुनते ही समाज अपना फैसला सुना देता है। 'दलबदल' ऐसा ही एक शब्द है। जैसे ही कोई विधायक या सांसद अपनी पार्टी छोड़ता है, उसे अवसरवादी, बिकाऊ या गद्दार घोषित कर दिया जाता है। किसी अदालत की जरूरत नहीं पड़ती, किसी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती। राजनीतिक दल और मीडिया पहले ही उसका चरित्र प्रमाणपत्र लिख देते हैं।

सवाल... क्या हर दलबदल गद्दारी है?

मेरा मानना है कि यह प्रश्न ही गलत है। सही प्रश्न यह है कि क्या लोकतंत्र में किसी व्यक्ति को अपना विचार बदलने का अधिकार है या नहीं? यदि उत्तर 'हां' है, तो फिर जनप्रतिनिधि इस अधिकार से वंचित क्यों हो?

लोकतंत्र का अर्थ केवल चुनाव नहीं है। उसका सबसे बड़ा आधार स्वतंत्र विवेक है। यदि किसी सांसद या विधायक का विवेक ही पार्टी नेतृत्व के पास गिरवी रख दिया जाए, तो वह जनता का प्रतिनिधि नहीं, केवल दल का प्रतिनिधि बनकर रह जाता है। तब संसद और विधानसभा विचार-विमर्श के मंच नहीं, बल्कि संख्या-बल के अखाड़े बन जाते हैं।

विडंबना देखिए! देश का सामान्य नागरिक सरकार की आलोचना कर सकता है, प्रधानमंत्री से असहमत हो सकता है और न्यायालय के निर्णय पर भी अपनी राय व्यक्त कर सकता है। लेकिन वही नागरिक यदि चुनाव जीतकर संसद या विधानसभा पहुंच जाए, तो उससे अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी अंतरात्मा को पार्टी व्हिप के हवाले कर दे। क्या यही लोकतंत्र है? दलबदल विरोधी कानून एक विशेष ऐतिहासिक परिस्थिति में बनाया गया था। उसका उद्देश्य जनप्रतिनिधियों की खरीद-फरोख्त रोकना था। इस उद्देश्य पर किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन समस्या वहां शुरू हुई जहाँ कानून ने खरीदे हुए विवेक और जागे हुए विवेक—दोनों को एक ही अपराध मान लिया।

यहीं मैं दलबदल, दिलबदल और अर्थबदल के बीच अंतर करता हूँ।

दिलबदल तब होता है जब किसी जनप्रतिनिधि की राजनीतिक समझ बदलती है। उसे लगता है कि उसकी पार्टी अपने घोषित सिद्धांतों से भटक गई है। उसकी अंतरात्मा किसी निर्णय का समर्थन करने से इनकार करती है और वह जनता के बीच जाकर नया जनादेश लेने को तैयार होता है। यह नैतिक बहस का विषय हो सकता है, लेकिन इसे स्वतः अपराध नहीं कहा जा सकता।

इसके विपरीत अर्थबदल वह है जहां विचार नहीं बदलते, केवल लाभ बदल जाता है। सत्ता, मंत्रीपद, धन या राजनीतिक सौदेबाजी के लिए होने वाला दलबदल लोकतंत्र की आत्मा पर हमला है। यदि लोकतंत्र को किसी चीज़ से सबसे बड़ा खतरा है, तो वह यही अर्थबदल है।

निस्संदेह एक कठिन प्रश्न उठता है—कैसे तय होगा कि किसी जनप्रतिनिधि का परिवर्तन अंतरात्मा की आवाज़ है या आर्थिक प्रलोभन का परिणाम? यह चुनौती वास्तविक है। लेकिन किसी सिद्धांत के दुरुपयोग की संभावना, उस सिद्धांत को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकती। न्याय व्यवस्था हत्या और आत्मरक्षा में अंतर करती है, भ्रष्टाचार और वैध निर्णय में अंतर करती है। उसी प्रकार लोकतंत्र को भी वैचारिक परिवर्तन और राजनीतिक खरीद-फरोख्त के बीच संवैधानिक कसौटी विकसित करनी होगी।

मेरा मानना है कि अब समय आ गया है कि दलबदल कानून की समीक्षा राजनीतिक सुविधा के आधार पर नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक दर्शन के आधार पर की जाए। यदि कोई जनप्रतिनिधि धन या पद के लिए दल बदलता है, तो उसकी सदस्यता तत्काल समाप्त होनी चाहिए और उसके सार्वजनिक जीवन पर कठोर दंड लगाया जाना चाहिए। लेकिन यदि कोई प्रतिनिधि वैचारिक असहमति के कारण जनता के बीच जाकर पुनः जनादेश लेने को तैयार है, तो लोकतंत्र को उससे डरना नहीं चाहिए।

लोकतंत्र में सबसे बड़ा अपराध दल बदलना नहीं है। सबसे बड़ा अपराध अपने विवेक को बेच देना है। दल बदलने से केवल सरकारें बदलती हैं, लेकिन विवेक बिक जाने से लोकतंत्र का चरित्र बदल जाता है। सरकारें फिर बन सकती हैं, पर चरित्र खो देने वाला लोकतंत्र उसकी कीमत पीढ़ियों तक चुकाता है।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के पूर्व किया योगाभ्यास

भोपाल। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के पूर्व आज टीटी नगर स्टेडियम में योगाभ्यास कार्यक्रम में आयोजित किया गया। इस दौरान केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ एवं आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन सचिव अशोक वर्षणे कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर हजारों की संख्या में युवाओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता कर स्वस्थ, सशक्त और जागरूक भारत के निर्माण का संकल्प लिया। वक्ताओं ने कहा कि योग केवल व्यायाम नहीं, बल्कि स्वस्थ शरीर, शांत मन और संतुलित जीवन का आधार है। इसे अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाकर स्वस्थ भारत के संकल्प को साकार करें। वहीं बड़े तालाब स्थित बोट क्लब पर भी आयोजित योगाभ्यास में महापौर मालती राय के साथ सहभागिता कर योग साधना की। प्राकृतिक सौंदर्य और सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण इस वातावरण में बड़ी संख्या में नागरिकों, युवाओं एवं योग साधकों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर स्वस्थ जीवन और निरोगी समाज के निर्माण का संकल्प लिया।

कंट्रोल रूम से परीक्षा केंद्र तक सीआरपीएफ के जवान पहुंचायेंगे प्रश्न पत्र

री-नीट: हर कदम पर निगरानी, हर केंद्र पर पहरा और अभ्यर्थियों के लिए लगेगी घड़ी

भोपाल, दोपहर मेट्रो।

मध्यप्रदेश में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी(एनटीए) की तरफ से आयोजित री-नीट परीक्षा रविवार 21 जून को होगी। प्रदेश के 30 जिलों में विशेष सुरक्षा के साथ परीक्षा आयोजित कराने की तैयारी की जा रही है। इस परीक्षा को लेकर मध्यप्रदेश उच्च सुरक्षा सतर्कता बरती जा रही है। इस संदर्भ में खास बात ये है कि कंट्रोल रूम से परीक्षा केंद्रों तक प्रश्न पत्र पहुंचाने की जिम्मेदारी सीआरपीएफ को सौंपी गयी है। राजधानी के 32 केंद्रों पर कैमरे और जैमर लगाए गए हैं। हर केंद्र पर साइबर कंमाडों समेत स्थानीय पुलिस गार्ड तैनात रहेंगे। हर एक केंद्र पर शासकीय डॉक्टर और एंबुलेंस तैनात रहेंगे, प्रत्येक परीक्षा केंद्र के बाहर बड़ी घड़ी लगाई जा रही है, ताकि मिनट-टू- मिनट तैयारियों पर नजर रखा सकें। जानकारी के अनुसार परीक्षा की तैयारियों को लेकर शनिवार को रिहर्सल होगी। पुनः परीक्षा के लिए कंट्रोल रूम से परीक्षा केंद्र तक सीआरपीएफ प्रश्न पत्र पहुंचाएगी। प्रदेश के 30 जिलों में 283 परीक्षा केंद्रों पर लगभग 1 लाख 18 हजार अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे।

रविवार को सोशल मीडिया पर रहेगी कमांडो की नजर

मध्यप्रदेश के गृह विभाग ने नीट परीक्षा के दौरान पूरे दिन सोशल मीडिया पर विशेष नजर रखेगी। अलग-अलग एप और साइट्स पर नजर रखने के लिए प्रदेश में 44 साइबर कमांडो तैनात किए गए हैं, जो हर सोशल मीडिया पर नीट परीक्षा को लेकर जारी होने वाले खबरों पर नजर रखेगी। सोशल मीडिया पर कोई अफवाह या दुष्प्रचार वायरल हुआ, तो तुरंत संबंधित के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

ये रहेंगे परीक्षा केंद्र

नीट परीक्षा को लेकर प्रदेश में इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, सागर, छिंदवाड़ा, बैतूल, भिंड, बालाघाट, अशोकनगर, छतरपुर, रतलाम, बड़वानी, खरगौन, धार, खंडवा, नर्मदापुरम्, दमोह, दतिया, देवास, गुना, मंदसौर, मुरैना, नीमच, राजगढ़, सिंगरौली, विदिशा और सतना परीक्षा केंद्र रहेंगे। सर्वाधिक परीक्षा केंद्र इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर शहर में बनाए गए हैं।

भोपाल में 32 केंद्रों पर परीक्षा

- री-नीट परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5.15 बजे तक परीक्षा होगी। भोपाल में 32 केंद्रों पर 13 हजार 774 स्टूडेंट्स परीक्षा देंगे।
- हर केंद्र पर डॉक्टर तैनात रहेंगे। किसी की तबीयत बिगड़ी, तो डॉक्टर वहीं मिलेंगे। स्टूडेंट्स के लिए हर सेंटर के बाहर एक बड़ी घड़ी लगाई जाएगी।
- परीक्षा केंद्रों पर दो-स्तरीय सुरक्षा मुख्य प्रवेश द्वार और अंदर पुलिस बल की तैनाती रहेगी।
- लड़कियों की जांच के लिए अलग से फ्रिस्किं तलाशी व्यवस्था की जाएगी।
- बिजली सप्लाई बाधित न हो, इसलिए जनरेटर उपलब्ध रहेंगे। केंद्रों में शौचालय और क्लॉक रूम की सुविधा हैं।
- अभिभावकों के लिए केंद्र के बाहर टेंट लगाए जाएंगे, ताकि उन्हें धूप और बारिश से राहत मिल सके।
- नीट परीक्षा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मध्यप्रदेश स्टेट साइबर मुख्यालय से 24 घंटे निगरानी रखी रही है।
- कंट्रोल रूम से परीक्षा केंद्र तक सीआरपीएफ प्रश्न पत्र को पहुंचाएगी। जिले के अफसर इसको लेकर मॉनिटरिंग करेंगे।
- प्रदेश गृह विभाग ने एडवाइजरी जारी कर दी है।

सामाजिक समरसता विकसित भारत की आधारशिला : नागर

मप्र बनेगा अभ्युदय की भूमि : डॉ. पांडव

भोपाल. दोपहर मेट्रो।

मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा आज सामाजिक समरसता के साथ विकसित भारत-2047 के संकल्प विषय पर समरसता विमर्श का आयोजन आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, शाहपुरा, भोपाल में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ परिषद के उपाध्यक्ष मोहन नागर, अखिल भारतीय संयोजक, सामाजिक समरसता गतिविधि श्याम प्रसाद, कार्यपालक निदेशक डॉ. बकुल लाड़ एवं प्राध्यापक एवं ख्यातिलब्ध समरसता विचारक डॉ. रमेश पांडव के सानिध्य में हुआ। परिषद के पूर्व महानिदेशक बी.आर. नायडू एवं महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविदयालय के कुलगुरु आलोक चौबे ने वीडियो के माध्यम से अपना उदबोधन दिया।

सामाजिक समरसता विकसित भारत की आधारशिला: श्री नागर ने कहा कि सामाजिक समरसता विकसित भारत की आधारशिला है। मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा मुख्यमंत्री डॉ. यादव के मार्गदर्शन में सामाजिक समरसता, नागरिक कर्तव्यों एवं संविधान जागरुकता से जुड़े अनेक कार्यक्रम प्रदेश भर में आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है और हम सभी एक ही भारत माता की संतान है। राम केवट मिलन, शबरी और भगवान राम का प्रसंग जैसे उदाहरण हमारी संस्कृति में समरसता के प्रेरक सूत्र है। अखिल भारतीय सामाजिक समरसता प्रमुख श्याम प्रसाद ने कहा कि समाज और गांव के विकास के लिए आपसी भाईचारा, सहयोग एवं सहभागिता आवश्यक है। जब समाज के सभी वर्ग मिलकर कार्य करते हैं. तभी वास्तविक विकास संभव होता है। उन्होंने संकल्प व्यक्त किया कि आने वाले वर्षों में मध्यप्रदेश के चयनित गांवों में म.प्र. जन अभियान परिषद के साथ मिलकर समरस समाज बनाने की दिशा में कार्य करेगा। समरसता विचारक डॉ. रमेश पांडव ने कहा कि समरसता का विचार भले ही महाराष्ट्र में प्रखरता से प्रारंभ हुआ हो, लेकिन मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के प्रयासों से मध्यप्रदेश समरसता के अभ्युदय की भूमि के रूप में प्रतिष्ठित होगा। परिषद द्वारा ग्रामोदय विश्वविदयालय के सहयोग से समरसता के विचार को अकादमिक रूप प्रदान किया गया है। जल्द ही इसका प्रभाव धरातल पर भी दिखाई देगा। डॉ. लाड़ ने कहा कि परिषद स्वैच्छिकता, सामूहिकता एवं स्वावलंबन के मूलमंत्र के साथ नवाचारों की प्रोत्साहक रही है। आज का समरसता विमर्श परिषद द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम के बीएसडब्ल्यू तथा एमएसडब्ल्यू पाठ्यक्रम के समीक्षा के लिये आयोजित की गई है। समीक्षा से निकले निष्कर्षों के आधार पर पाठ्यक्रम प्रभावी और रोचक बनाने की दिशा में प्रयास किया जायेगा।

रेल नेटवर्क द्वारा राख की ढुलाई के लिए की जा रही है हरित पहल

भोपाल. दोपहर मेट्रो।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में रेल नेटवर्क के माध्यम से राख की ढुलाई के बड़े पैमाने पर परिवहन को सक्षम बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल पर चर्चा की गई। उद्देश्य सरल लेकिन परिवर्तनकारी है। राख की ढुलाई को बिजली संयंत्रों से उद्योगों तक कुशलतापूर्वक पहुँचाना, जहाँ इसका उपयोग सड़कों के निर्माण, ईंटों के उत्पादन, सीमेंट उत्पादन और देश भर में अवसंरचना विकास में किया जा सकता है। बैठक में रेल राज्य मंत्री वी. सोमन्ना और रवनीत सिंह बिट्टू भी उपस्थित थे।

थर्मल पावर प्लांटों से प्रतिवर्ष लगभग 340 करोड़ टन उड़ने वाली राख उत्पन्न होती है। दशकों से यह भारी राख चिमनियों के आसपास जमा रहती थी। अब भारतीय रेलवे एक हरित पहल के माध्यम से इसे बदल रहा है, जिसके अंतर्गत विशेष कंटेनरों और रेल गलियारों का एक समर्पित लॉजिस्टिक्स नेटवर्क बनाया जा रहा है। यह नेटवर्क अपशिष्ट पदार्थ को उसके उत्पादन स्थल से उसके जरूरत वाले स्थल तक पहुंचाएगा।

बिजली संयंत्र जो कचरा फेंकता है, सीमेंट संयंत्र उसे सहेज कर रखता है। राख को सही ढंग से स्थानांतरित और उपयोग करने से सीमेंट, कंक्रीट, ब्लॉक और बोर्ड बनाने का कच्चा माल प्राप्त होता है। सस्ती राख का मतलब है सस्ती ईंटें, सीमेंट की कम कीमतें और अंततः शहरी और ग्रामीण भारत में आवास की सुलभता में वृद्धि। रेलगाड़ियों और विशेष रूप से निर्मित लॉजिस्टिक्स प्रणालियों के भीतर समाहित, उड़ने वाली राख की ढुलाई उचित तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जाती है, और एक प्रदूषक के रूप में नहीं बल्कि भारत के बुनियादी ढांचे के विकास में एक उत्पादक भागीदार के रूप में पहुंचती है।

मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी ने बनाई तकनीकी निगरानी व्यवस्था

भोपाल. दोपहर मेट्रो।

मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी ने अपने ताप एवं जल विद्युत गृहों के अधिक सुरक्षित, दक्ष और निर्बाध संचालन के लिए नई तकनीकी निगरानी व्यवस्था लागू की है। कंपनी के प्रबंध संचालक मनजीत सिंह ने बताया कि वार्षिक रखरखाव और पूंजीगत रखरखाव कार्यों के बाद बिजली उत्पादन इकाइयों के प्रदर्शन की प्रभावी निगरानी के लिए मुख्यालय तथा विद्युत गृहों के अनुभवी और युवा अभियंताओं की संयुक्त समन्वय टीम गठित की गई है। यह टीम रखरखाव कार्यों की योजना, निरीक्षण, गुणवत्ता, मूल्यांकन और अनुपालन की निरंतर निगरानी करेगी। वर्तमान में कंपनी

5492 मेगावाट बिजली उत्पादन को मिलेगी अब नई मजबूती

चार ताप विद्युत गृहों से 4570 मेगावाट, दस जल विद्युत गृहों से 915 मेगावाट तथा रतागुरड़िया सौर ऊर्जा परियोजना से 7 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रही है। इस प्रकार कंपनी की कुल स्थापित उत्पादन क्षमता 5492 मेगावाट है। नई व्यवस्था के तहत गठित टीमें नियमित रूप से विद्युत गृहों का निरीक्षण करेंगी, पूर्व में आई तकनीकी बाधाओं के कारणों का विश्लेषण कर आवश्यक सुधार सुनिश्चित करेंगी तथा रखरखाव कार्यों की गुणवत्ता और दैनिक प्रगति की समीक्षा करेंगी। प्रत्येक कार्य की गुणवत्ता का सत्यापन भी किया जाएगा। कंपनी का मानना है कि यह पहल तकनीकी विशेषज्ञता, पारदर्शिता और नवाचार को बढ़ावा देकर बिजली उत्पादन की विश्वसनीयता बढ़ाएगी, संयंत्रों की कार्यक्षमता में सुधार करेगी तथा उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

नकली घी को देसी बताकर बेचने वाले चार आरोपी बरी

भोपाल. दोपहर मेट्रो।

भोपाल कोर्ट ने नकली घी में देसी घी की खुशबू मिलाकर बेचने के चार आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने सुनवाई के दौरान स्वीकार किया कि जब्त किए गए कई डिब्बों पर घी नहीं, बल्कि दीपक जलाने वाले द्रव्य (दीपक लिक्विड) और पूजा सामग्री संबंधी उपयोग का उल्लेख था।

कोर्ट ने यह भी नोट किया कि जांच एजेंसियां किसी ऐसे ग्राहक, बिल या रसीद को पेश नहीं कर सकीं, जिससे साबित हो कि आरोपियों ने उक्त सामग्री को घी बताकर बेचा था। पुलिस ने इस मामले में अमित तलेरजा, राहुल मीणा, राकेश मीणा और शंकरलाल बत्रा को आरोपी बनाया गया था। घटना हनुमानगंज थाना क्षेत्र की 6 नवंबर 2020 की है। खाद्य विभाग की टीम ने जुमेराती में गल्ला बाजार के पास एक मकान में नकली घी बनाने वालों को पकड़ा था। पुलिस का आरोप था कि आरोपी नकली घी में देसी घी के एसेंस मिला रहे हैं। इसके बाद इसे बाजार में लोगों को देसी घी बताकर बेच रहे हैं।

सुनवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी भोजराज सिंह धाकड़ ने स्वीकार किया कि शासन ने उन्हें केवल खाद्य पदार्थों की जांच के लिए अधिकृत किया है। उन्होंने यह भी माना कि जो पदार्थ खाद्य योग्य नहीं हैं, उनकी जांच करने का उन्हें अधिकार नहीं है। कोर्ट ने पाया कि जब्त किए गए डिब्बों पर घी या खाद्य पदार्थ नहीं, बल्कि दीपद्रव्य (दीपक जलाने वाला पदार्थ) लिखा था। साथ ही उन पर पूजा-पाठ और हवन सामग्री में उपयोग का उल्लेख भी था।

गायत्री फूड के सीईओ के खिलाफ ईडी ने दायर की शिकायत

भोपाल. दोपहर मेट्रो।

फर्जी प्रयोगशाला रिपोर्ट का उपयोग कर मिलावटी डेयरी उत्पादों का निर्माण और निर्यात करने वाली भोपाल की जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स के सीईओ सुनील कुमार त्रिपाठी एवं अन्य के विरुद्ध प्रवर्तन निदेशालय, भोपाल की टीम ने विशेष न्यायालय (धनशोधन निवारण अधिनियम) के समक्ष एक और पूरक अभियोजन शिकायत (एसपीई) दायर की है। न्यायालय ने आरोपियों को पेश होने के लिए नोटिस भी जारी किए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में भोपाल के हबीबगंज पुलिस स्टेशन और आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) भोपाल द्वारा मेसर्स जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (जेजीएफपीएल) से जुड़े निदेशकों, अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर आधार पर जांच शुरू की थी।

मेट्रो एंकर रुद्राक्ष किंग्सटन, बावड़िया कला में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा हवन-पूजन के साथ संपन्न

भागवत वह औषधालय है, जिसकी शरण में जाने से दूर होते हैं कष्ट

भोपाल. दोपहर मेट्रो।

'भागवत वह औषधालय है, जिसकी शरण में जाने से सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। प्रतिदिन भागवत कथा सुनेंगे तो यह आपको पाप नहीं करने देगी। भगवान स्वयं भी नियमित रूप से ब्राह्मणों से वेद और पुराणों की कथा परिवार सहित सुनते हैं। इसलिए अपने बच्चों को कथा अवश्य सुनाएं, उनका मनोबल बढ़ेगा।'

ये उद्गार कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर महाराज ने बावड़िया कला के रुद्राक्ष किंग्सटन परिसर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के विश्राम दिवस पर व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि कन्हैया से रिश्ता बनाओगे तो वह आपका बेड़ा पार कर देंगे। सांसारिक लोग फंसा देंगे। ये तभी तक प्रेम करते हैं, जब तक आप उनकी जरूरतें पूरी करते हैं। शालिग्राम डेवलपर्स रुद्राक्ष किंग्सटन के सहयोग से आयोजित कथा के विश्राम दिवस पर महाराज जी ने द्वारिका लीला, सुदामा चरित्र और परीक्षित मोक्ष का हृदयस्पर्शी प्रसंग सुनाया। महाराज ने विभिन्न प्रसंगों में कई मनोहारी भजन सुनाए। 'जगत सब छोड़ दिया, सांवरे तेरे पीछे...' इस पर श्रोता भावविभोर होकर नृत्य करने लगे। कथा आयोजक और यजमान शालिग्राम डेवलपर्स के सीएमडी देवेंद्र चौकसे, संगीता चौकसे, वीरेंद्र चौकसे, अनीता चौकसे, प्रेम नारायण चौकसे और पूरा परिवार भागवत जी की आरती और हवन-पूजन में शामिल हुआ। भोपाल के सांसद आलोक शर्मा ने कथा विश्राम के बाद व्यास की आरती की। इस अवसर पर उन्होंने कथाओं के आयोजन के लिए स्थायी पंडाल बनाए जाने की बात कही। इसके लिए उन्होंने 50 लाख रुपये दिए जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि श्री देवकीनंदन ठाकुर महाराज सनातन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आयोजक देवेंद्र चौकसे से आग्रह किया कि अगले वर्ष भी महाराज जी की कथा इसी प्रांगण में कराई जाए। कथा में हजारों श्रद्धालु कथा सुनने पहुंचे।

महंगाई का तगड़ा झटका, बाजार में हरी सब्जियों की आवक घटी

गर्मी और सुस्त मानसून ने बिगाड़ा किचन का बजट,सब्जियों के दाम आसमान पर

भोपाल/इंदौर, दोपहर मेट्रो

भीषण गर्मी और मानसून की धीमी रफ्तार का असर अब सीधे आम आदमी की रसोई पर दिखाई देने लगा है। प्रदेश में हरी सब्जियों की आवक लगातार घटने से बाजार में उनके दाम तेजी से बढ़ गए हैं। टमाटर, गिलकी, लौकी, पालक और बैंगन जैसी रोजमर्रा की सब्जियां आम लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। मंडियों में मांग के मुकाबले आपूर्ति बेहद कम होने से कीमतों में लगातार उछाल बना हुआ है।

भोपाल में मानसून की शुरुआत और स्थानीय आवक घटने के कारण सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। थोक मंडियों में कमी के चलते टमाटर के भाव खुदरा बाजारों में 70 से 80 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। भिंडी, गवार फली और हरी मिर्च जैसी अन्य हरी सब्जियों की कीमतों में भी भारी उछाल आया है। टमाटर जहां 70 - 80 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, तो वहीं हरी मिर्चर्ू 40 - 60, भिंडी 40 - 60, गवार फली 40 -50, गिल्की 60-80 रुपए प्रति किलो बिक रही है।

सबसे ज्यादा असर टमाटर की कीमतों पर

इंदौर की चोइथराम मंडी के व्यापारियों के अनुसार सबसे अधिक असर टमाटर की कीमतों पर पड़ा है। खुदरा बाजार में टमाटर 60 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। वहीं गिलकी और बैंगन 60 रुपए किलो, जबकि लौकी और पालक 40 से 50 रुपए प्रति किलो बिक रहे हैं। लगातार बढ़ती कीमतों ने गृहिणियों और मध्यमवर्गीय परिवारों का बजट बिगाड़ दिया है।

राजस्थान से सप्लाई बंद होने का बड़ा असर

सब्जियों की महंगाई के पीछे सबसे बड़ा कारण पड़ोसी राज्यों से होने वाली आपूर्ति में आई भारी कमी है। सामान्य परिस्थितियों में राजस्थान से बड़ी मात्रा में सब्जियां मध्यप्रदेश की मंडियों में पहुंचती हैं, लेकिन इस बार भीषण गर्मी के कारण वहां की फसलें समय से पहले ही खराब हो गईं। परिणामस्वरूप राजस्थान से आने वाली सब्जियों की सप्लाई लगभग ठप हो गई है।

महाराष्ट्र की फसलें भी प्रभावित

राजस्थान से आपूर्ति रुकने के बाद अब प्रदेश की मंडियां महाराष्ट्र पर निर्भर हो गई हैं। इंदौर सहित कई शहरों में कन्नड़, चालीसगांव, संभाजीनगर और कलवन क्षेत्रों से सब्जियां मंगाई जा रही हैं। हालांकि वहां भी अत्यधिक गर्मी के कारण उत्पादन प्रभावित हुआ है। विशेष रूप से टमाटर उत्पादकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिससे बाजार में उपलब्धता और कम हो गई है।

मंडी में सुविधाओं का अभाव बढ़ा रहा संकट

व्यापारियों का कहना है कि इंदौर मंडी में पर्याप्त शेड और भंडारण सुविधाएं नहीं होने से बड़ी मात्रा में सब्जियां खराब हो रही हैं। तेज धूप में खुले में रखी सब्जियां जल्दी सड़ जाती हैं, जिससे नुकसान बढ़ता है और कीमतों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। यदि मंडी में बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों तो काफी हद तक बर्बादी रोकी जा सकती है। चोइथराम मंडी में सामान्य दिनों में जहां रोजाना 100 से 200 गाड़ियां सब्जियां पहुंचती थीं, वहीं वर्तमान में केवल 20 से 25 गाड़ियां ही आ रही हैं। मांग और आपूर्ति के इस बड़े अंतर ने सब्जियों की कीमतों को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है।

डिफेंस मैन्युफेक्चरिंग को नई गति देने पर राज्य स्तरीय कार्यशाला में मंथन

भोपाल। रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के उप महानिदेशक (स्वदेशीकरण) सुशील कुमार सतपुते ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य तभी साकार होगा, जब उद्योग, एमएसएमई, स्टार्टअप, अनुसंधान संस्थान और शिक्षण संस्थाएं एक साझा मंच पर आकर नवाचार आधारित रक्षा विनिर्माण को आगे बढ़ाएंगी। उन्होंने कहा कि राज्यों में मजबूत औद्योगिक एवं नवाचार आधारित इको सिस्टम विकसित करना समय की आवश्यकता है और केंद्र व राज्यों के समन्वित प्रयासों से ही देश रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बन सकेगा।

रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 20-21 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आत्मनिर्भरता इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग : प्रमोटिंग स्टेट-लेवल इकोसिस्टम्स÷ की तैयारियों के तहत मध्यप्रदेश शासन द्वारा एमपीआईडीसी मुख्यालय, भोपाल में तीसरे चरण के अंतर्गत राज्य स्तरीय फ्लैगशिप परामर्श कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता, स्वदेशीकरण, एमएसएमई, स्टार्टअप, नवाचार तथा उद्योग-अकादमिक सहयोग को मजबूत बनाने पर विस्तृत विचार-विमर्श हुआ।

मप्र में सरकारी फिजूलखर्ची पर ब्रेक

विभागीय सचिवों को प्रदेश से बाहर जाने सीएस की लेनी होगी मंजूरी

बैठकों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को प्राथमिकता दी जाएगी

प्राकृतिक खेती और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए व्यापक अभियान चलेगा

भोपाल, दोपहर मेट्रो

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग और ऊर्जा संरक्षण के आह्वान के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने शासकीय कार्यप्रणाली में मितव्ययता बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। अब विभागीय सचिवों को प्रदेश के बाहर शासकीय यात्रा करने से पहले मुख्य सचिव की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। साथ ही अधिकारियों-कर्मचारियों की अनावश्यक यात्राओं पर भी नियंत्रण रखा जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सभी विभागाध्यक्षों और कलेक्टरों को जारी निर्देशों में कहा गया है कि बैठकों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सेमिनारों का आयोजन यथासंभव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाए, ताकि समय और संसाधनों दोनों की बचत हो सके।

मुख्यमंत्री पहले ही दे चुके हैं उदाहरण- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्वयं अपने सरकारी काफिले को 13 वाहनों से घटाकर 7 वाहन कर दिया है और उसमें इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल किया है। इसके साथ ही सरकारी कार्यक्रमों में वाहनों के सीमित उपयोग के निर्देश भी पहले से लागू हैं।

सार्वजनिक परिवहन और कार-पूलिंग को बढ़ावा

निर्देशों के अनुसार अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यालय आने-जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन, कार-पूलिंग और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। केंद्र सरकार से जुड़े मामलों के लिए नई दिल्ली और मुंबई स्थित आवासीय आयुक्त कार्यालयों की मदद लेने पर भी जोर दिया गया है।

ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष फोकस

सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने, रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग, पाइप्ड नेचुरल गैस नेटवर्क के विस्तार और उज्ज्वला योजना के डुप्लीकेट व अपात्र कनेक्शनों की पहचान के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। निर्माण विभागों को पर्यावरण अनुकूल निर्माण सामग्री के उपयोग और उसके प्रचार-प्रसार की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

सोलर पैनल और जन-जागरूकता अभियान

सभी विभागों को प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत घरों की छतों पर सौर ऊर्जा पैनल लगाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जनसंपर्क विभाग मेरा भारत-मेरा योगदान जैसे जन-जागरूकता अभियान चलाकर ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का संदेश देगा। खनिज साधन विभाग को लिथियम, कोबाल्ट, रेयर अर्थ, कॉपर और कोयला जैसे रणनीतिक खनिजों की स्वीकृतियों और लीज प्रक्रिया को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि आयात पर निर्भरता कम हो सके।

10 दिन में सभी विभागों से मांगी जानकारी

जीडीए ने पूछा- कौन IAS कब-कहां रहा पदस्थ, बताना होगा कितना मिला वेतन

भोपाल, दोपहर मेट्रो

मध्य प्रदेश के अलग-अलग विभागों और जिलों में कौन से आईएएस अफसर कब से कब तक पदस्थ रहे हैं और इस दौरान उन्हें कितना वेतन मिलता रहा है? उनके वेतन से कितनी राशि की कटौती की जाती रही है। सेवा काल के दौरान कितने अवकाश उनके द्वारा लिए गए हैं। राज्य सरकार इसकी जानकारी जुटा रही है। इसको लेकर सभी विभागों और विभागाध्यक्षों को पत्र लिखकर 30 जून तक जानकारी भेजने के लिए कहा गया है।

प्रदेश के सामान्य कर्मचारी की पेंशन और अन्य वेतन भत्तों के निराकरण में सरकार भले ही समय पर एक्शन नहीं ले पाए और कर्मचारियों अधिकारियों को अपना भुगतान पाने के लिए इंतजार करना पड़े लेकिन आईएएस अधिकारियों के मामले में किसी तरह की ढील नहीं होनी चाहिए। आईएएस अफसर का सर्विस रिकॉर्ड पूरी तरह से मेंटेन रहे, इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने सर्कुलर जारी कर कहा है कि सभी अधिकारी अपना तीन साल का पूरा हिसाब किताब खुद देंगे ताकि विभाग उनके सभी प्रकरणों का निराकरण समय पर कर सके।

सामान्य प्रशासन विभाग ((जीएडी) से जारी निर्देश में कहा है कि प्रदेश के सभी आईएएस अधिकारियों का वर्ष 2023 से 2026 तक का सेवा सत्यापन ब्यौरा चाहिए। इसके लिए जीएडी ने सभी विभागों एवं कार्यालय प्रमुखों को निर्देश जारी करते हुए 30 जून 2026 तक आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है।

वर्ष 2023 से 2026 तक का मांगा ब्यौरा

सामान्य प्रशासन विभाग ने आईएएस अधिकारियों से वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 का डिटेल सेवा सत्यापन विवरण मांगा है। इसके लिए एक फॉर्मेट भी जारी किया है, जिसमें संबंधित अधिकारियों को वेतन भुगतान, भत्तों और कटौतियों की माहवार जानकारी दर्ज करनी होगी। इसके अलावा इन वर्षों के दौरान अधिकारियों की पदस्थापना, स्थानांतरण, अवकाश अवधि तथा अन्य सेवा संबंधी विवरण भी फार्मेट में शामिल किए जाएंगे। बताया जाता है कि समयसीमा के भीतर जानकारी उपलब्ध कराना सभी विभागों और कार्यालय प्रमुखों के लिए अनिवार्य किया है।

मप्र में अवैध कॉलोनियों पर शिकंजा कसेगी सरकार

विधानसभा के मानसून सत्र में पेश होगा सख्त कानून, 10 साल तक की सजा का प्रावधान

भोपाल, दोपहर मेट्रो

भोपाल। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश में अवैध कॉलोनियों के बढ़ते विस्तार को रोकने के लिए राज्य सरकार अब सख्त कदम उठाने की तैयारी में है। आगामी मानसून सत्र में सरकार एक नया विधेयक पेश करने जा रही है, जिसमें अवैध कॉलोनी विकसित करने वालों के खिलाफ कठोर दंडात्मक प्रावधान शामिल होंगे। प्रस्तावित कानून के अनुसार दोषी पाए जाने पर 7 से 10 वर्ष तक की जेल और 2 से 3 करोड़ रुपये तक के भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

सरकार का कहना है कि अवैध कॉलोनियों के कारण नागरिकों को बुनियादी सुविधाओं जैसे सड़क, पानी, बिजली और सीवरेज जैसी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है। साथ ही शहरी विकास की योजनाएं भी प्रभावित होती हैं, जिससे शहरों का संतुलित विकास बाधित होता है।

किन क्षेत्रों में कॉलोनी निर्माण अवैध माना जाएगा?

प्रस्तावित विधेयक में स्पष्ट किया गया है कि शासकीय भूमि, ि वकास प्राधिकरणों की जमीन, स्थानीय निकायों की संपत्ति, वन भूमि, जल स्रोतों, नदियों-तालाबों, पार्कों, खेल मैदानों और अन्य प्रतिबंधित क्षेत्रों में विकसित की गई कॉलोनियों को अवैध माना जाएगा। ऐसे मामलों में कॉलोनी विकसित करने वालों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाएगी।

शिक्षा एवं नवाचार को नई उड़ान

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में आई.आई.एम. नागपुर और आई.आई.एम. इंदौर के मध्य महत्वपूर्ण एमओयू संपन्न हुआ। यह समझौता प्रबंधन शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार और नेतृत्व विकास के क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ करेगा। दोनों संस्थानों के बीच ज्ञान, संसाधनों और विशेषज्ञता का आदान-प्रदान विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों के लिए नए अवसरों का मार्ग प्रशस्त करेगा। यह पहल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्षमता निर्माण तथा उत्कृष्ट शैक्षणिक वातावरण को बढ़ावा देने के साथ-साथ मध्यप्रदेश को शिक्षा और नवाचार के अग्रणी केंद्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

15 जून से मंडी शुल्क फिर 1.5 फीसदी हुआ

कागजों में व्यापारी भरेंगे टैक्स पर कटेगी किसान की जेब!

भोपाल, दोपहर मेट्रो

राज्य सरकार ने कृषि उपज मंडियों में लगने वाले शुल्क को फिर बढ़ाकर 1.5 प्रतिशत कर दिया है। कागजों में यह शुल्क व्यापारी और खरीदारों से वसूला जाएगा, लेकिन किसान संगठनों का आरोप है कि इसकी असली कीमत आखिरकार किसानों को ही चुकानी पड़ेगी। उनका कहना है कि मंडियों में कारोबार की लागत बढ़ने पर व्यापारी उसकी भरपाई किसानों की उपज के भाव में कटौती कर करेंगे।

ऐसे में जिस किसान को अपनी फसल का बेहतर दाम मिलने की उम्मीद रहती है, उसकी जेब पर ही इस फैसले का असर पड़ सकता है। खास बात यह है कि करीब ढाई साल पहले 6 अक्टूबर

2023 को सरकार ने किसानों और व्यापारियों को राहत देने का हवाला देते हुए मंडी शुल्क 1.5 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत किया था, जिसे अब फिर बढ़ा दिया गया है। बढ़ा हुआ शुल्क 15 जून से लागू हो गया है। मंडी शुल्क के डेढ़ रुपए में से 75 पैसे सीधे राज्य स्तर की विभिन्न योजनाओं में जाएंगे। इनमें किसान सड़क निधि, कृषि अनुसंधान एवं अधोसंरचना विकास, गौ संवर्धन और मुख्यमंत्री कृषक कल्याण जैसी योजनाएं शामिल हैं।

मेट्रो एंकर बेस्ट ऑफ फाइव समाप्त होने के बाद लिया गया फैसला, अब अंग्रेजी का डर होगा दूर

प्रदेश में 9वीं-10वीं के छात्र चुन सकेंगे बेसिक या स्टैंडर्ड

भोपाल, दोपहर मेट्रो

मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) ने कक्षा 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी विषय में भी गणित की तर्ज पर दो विकल्प बेसिक और स्टैंडर्ड लागू करने का निर्णय लिया है। मंडल द्वारा इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

नई व्यवस्था के तहत सत्र 2026-27 से कक्षा 9वीं और सत्र 2027-28 से कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को अपनी क्षमता और आवश्यकता के अनुसार अंग्रेजी विषय का चयन करने का अवसर मिलेगा। माशिमं के अनुसार यह निर्णय नई शिक्षा नीति के अनुरूप विद्यार्थियों को विकल्प आधारित शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे विद्यार्थियों को अंग्रेजी विषय के अध्ययन में अधिक लचीलापन मिलेगा और वे अपनी शैक्षणिक जरूरतों के अनुसार विषय का स्तर चुन सकेंगे। मंडल ने सभी संबंधित विभागों और विद्यालयों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश भी जारी कर दिए हैं।

एक ही किताब, लेकिन अलग होंगे प्रश्नपत्र- मंडल ने स्पष्ट किया है कि बेसिक और स्टैंडर्ड अंग्रेजी की पाठ्यपुस्तक एक ही होगी और दोनों वर्गों की कक्षाएं भी साथ लगेंगी। विद्यार्थियों को केवल नामांकन के समय अपनी पसंद का विकल्प चुनना होगा। हालांकि, दोनों के प्रश्नपत्र अलग-अलग होंगे। प्रश्नपत्रों का निर्माण माशिमं द्वारा जारी सैंपल पेपर और अंक योजना के आधार पर किया जाएगा और दोनों का कठिनाई स्तर अलग रहेगा।

बेस्ट ऑफ फाइव समाप्त होने के बाद लिया गया फैसला- स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इस सत्र से कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में बेस्ट ऑफ फाइव योजना समाप्त की जा रही है। ऐसे में परिणामों पर संभावित प्रभाव को देखते हुए अंग्रेजी और गणित में दो विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। अभी तक बेस्ट ऑफ फाइव योजना के तहत सबसे अधिक लाभ अंग्रेजी और गणित विषय में विद्यार्थियों को मिलता था।

कमजोर विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ

शिक्षाविद उषा खरे का कहना है कि अंग्रेजी बेसिक और स्टैंडर्ड का विकल्प मिलने से विद्यार्थियों पर अनावश्यक शैक्षणिक दबाव कम होगा। इससे कमजोर विद्यार्थियों को भी अंग्रेजी विषय में बेहतर प्रदर्शन का अवसर मिलेगा और वे अपनी रुचि तथा भविष्य की शैक्षणिक आवश्यकताओं के अनुसार विषय का चयन कर सकेंगे।

इस सत्र से नौवीं कक्षा में गणित की तरह अंग्रेजी के भी दो विकल्प - बेसिक और स्टैंडर्ड उपलब्ध होंगे। अगले सत्र से 10वीं में लागू होगा। - **बुद्धेश कुमार वैद्य**, सचिव, माशिमं

स्क्रीन के उस पार का जाल

डिजिटल क्रांति ने भारत को अभूतपूर्व अवसर दिए हैं। शिक्षा, व्यापार, मनोरंजन और संवाद-हर क्षेत्र में तकनीक ने नई संभावनाओं के द्वार खोले हैं। इतिहास बताता है कि हर नई तकनीक अपने साथ कुछ ऐसे जोखिम भी लेकर आती है, जिनकी पहचान अक्सर तब होती है जब नुकसान समाज के सामने स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। ऑनलाइन गेमिंग का संसार भी इसी विरोधाभास का उदाहरण बन चुका है। कुछ वर्ष पहले तक मोबाइल पर खेले जाने वाले खेल केवल मनोरंजन का साधन माने जाते थे। धीरे- धीरे यह उद्योग इतना विस्तृत हो गया कि करोड़ों लोग इसके दायरे में आ गए। जीत का रोमांच कमाई के लालच में बदल गया और मनोरंजन का मंच कई लोगों के लिए आर्थिक संकट का कारण बन गया। हजारों परिवारों ने अपनी बचत गंवाई, युवाओं में लत की प्रवृत्ति बढ़ी और मानसिक तनाव से जुड़े मामलों ने समाज को झकझोरना शुरू किया। इसी पृष्ठभूमि में लागू किए गए नए नियम केवल एक कानूनी हस्तक्षेप नहीं, बल्कि डिजिटल समाज को सुरक्षित बनाने की कोशिश के रूप में देखे जाने चाहिए। सरकार ने स्पष्ट संकेत दिया है कि नवाचार का स्वागत है, लेकिन उसके नाम पर अनियंत्रित जोखिमों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि धन-आधारित ऑनलाइन खेलों पर कठोर नियंत्रण के साथ-साथ ई-स्पोर्ट्स और सामाजिक सहभागिता वाले डिजिटल खेलों के लिए अलग रास्ता तैयार किया गया है। इस नीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह केवल प्लेटफॉर्म संचालकों को नहीं, बल्कि पूरे डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को जवाबदेह बनाने का प्रयास करती है। विज्ञापन, भुगतान व्यवस्था और ऑनलाइन सेवाओं की निगरानी को जोड़कर यह समझने की कोशिश की गई है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था में किसी भी गतिविधि का प्रभाव उसके घोषित उद्देश्य से कहीं अधिक व्यापक हो सकता है। यदि किसी मंच से सामाजिक या आर्थिक नुकसान उत्पन्न हो रहा है, तो उसकी जवाबदेही केवल उपयोगकर्ता पर नहीं छोड़ी जा सकती। हालांकि किसी भी कानून की वास्तविक परीक्षा उसके क्रियान्वयन में होती है। इंटरनेट की दुनिया सीमाहीन है, जबकि कानून अक्सर भौगोलिक सीमाओं के भीतर काम करते हैं। ऐसे में अवैध प्लेटफॉर्मों पर प्रभावी नियंत्रण, तकनीकी निगरानी और त्वरित शिकायत निवारण व्यवस्था इस पूरी पहल की सफलता तय करेंगे।

पश्चिम एशिया में समकालीन भू-राजनीतिक बदलाव और भारत की भूमिका

डॉ. सत्यवान सौरभ
स्वतंत्र टिप्पणीकार

पश्चिम एशिया आज विश्व राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्रों में से एक है। यह क्षेत्र वैश्विक ऊर्जा संसाधनों का केंद्र होने के साथ-साथ एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ने वाला सामरिक भूभाग भी है। पिछले दो दशकों में इस क्षेत्र में हुए युद्धों, शासन परिवर्तनों, सांप्रदायिक संघर्षों, आतंकवाद के उभार तथा बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेपों ने इसकी राजनीतिक संरचना को गहराई से प्रभावित किया है। इराक, सीरिया, लीबिया और यमन जैसे देशों के अनुभवों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सैन्य शक्ति के माध्यम से राजनीतिक स्थिरता स्थापित करने के प्रयास अक्सर अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाते। इसी बीच खाड़ी देशों, ईरान तथा वैश्विक शक्तियों के बीच संबंधों में आए बदलाव पश्चिम एशिया में एक नई क्षेत्रीय व्यवस्था के निर्माण की ओर संकेत करते हैं। ऐसे परिवर्तनों के बीच भारत के लिए भी अपनी विदेश नीति को नए सिरे से परिभाषित करना आवश्यक हो गया है क्योंकि इस क्षेत्र से उसके ऊर्जा, व्यापारिक और प्रवासी हित गहराई से जुड़े हुए हैं।

शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद पश्चिम एशिया में अमेरिका का प्रभाव लगभग निर्विवाद था। अमेरिका ने लोकतंत्र, सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी अभियानों के नाम पर इराक तथा अफगानिस्तान में सैन्य हस्तक्षेप किए। किंतु इराक युद्ध के परिणामों ने यह दिखाया कि शासन परिवर्तन के बाद भी स्थायी शांति और संस्थागत स्थिरता सुनिश्चित नहीं की जा सकती। सद्दाम हुसैन के पतन के बाद इराक में सांप्रदायिक तनाव बढ़ा, राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुई और अंततः इस्लामिक स्टेट (आईएसआईएस) जैसे आतंकी संगठन का उदय हुआ। इसी प्रकार लीबिया में नाटो समर्थित हस्तक्षेप ने तत्कालीन शासन को तो समाप्त कर दिया, किंतु देश वर्षों तक गृहयुद्ध और अराजकता में फँसा रहा। सीरिया में विभिन्न वैश्विक और क्षेत्रीय शक्तियों की सैन्य भागीदारी ने संघर्ष को और जटिल बना दिया। इन घटनाओं ने सिद्ध कर दिया कि सैन्य हस्तक्षेप राजनीतिक समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हो सकते।

पश्चिम एशिया में बदलती भू-राजनीति का एक प्रमुख पहलू अमेरिका के प्रभाव में अपेक्षाकृत कमी और नई शक्तियों के उदय के रूप में सामने आया है। अमेरिका अब अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं को हिंद-प्रशांत क्षेत्र और चीन के उदय की ओर स्थानांतरित कर रहा है। परिणामस्वरूप पश्चिम एशिया में एक प्रकार का शक्ति शून्य उत्पन्न हुआ है, जिसे क्षेत्रीय और अन्य वैश्विक शक्तियाँ भरने का प्रयास कर रही हैं। चीन ने आर्थिक निवेश, व्यापारिक संबंधों और बेल्ट एंड रोड पहल के माध्यम से अपनी उपस्थिति मजबूत की है। विशेष रूप से सऊदी अरब और ईरान के बीच संबंधों की बहाली में चीन की मध्यस्थता ने यह संकेत दिया कि कूटनीतिक और आर्थिक साधन अब क्षेत्रीय स्थिरता के लिए सैन्य शक्ति से अधिक प्रभावी हो सकते हैं। रूस ने भी सीरिया में हस्तक्षेप के माध्यम से अपनी रणनीतिक वापसी दर्ज कराई और यह प्रदर्शित किया कि सीमित सैन्य उपस्थिति तथा सक्रिय कूटनीति के संयोजन से क्षेत्रीय प्रभाव स्थापित किया जा सकता है।

इसी दौरान खाड़ी देशों की विदेश नीति में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिले हैं। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर जैसे देशों ने आर्थिक विकास, निवेश और तकनीकी आधुनिकीकरण को प्राथमिकता देना शुरू किया है। सऊदी अरब का 'विजन 2030' कार्यक्रम इस परिवर्तन का प्रतीक है, जिसका उद्देश्य तेल पर निर्भरता कम कर अर्थव्यवस्था का विविधीकरण करना है। इसके लिए क्षेत्रीय स्थिरता आवश्यक है। यही कारण है कि खाड़ी देशों ने ईरान के साथ तनाव कम करने तथा संवाद बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए हैं। दूसरी ओर ईरान, जो लंबे समय तक अमेरिकी प्रतिबंधों और क्षेत्रीय अलगाव का सामना करता रहा, अब क्षेत्रीय शक्ति संतुलन का एक अनिवार्य घटक बनकर उभरा है। इराक, सीरिया, लेबनान और यमन में उसका प्रभाव इस तथ्य को रेखांकित करता है कि पश्चिम एशिया की किसी भी सुरक्षा व्यवस्था को ईरान को शामिल किए बिना सफल नहीं बनाया जा सकता।

वर्तमान परिस्थितियाँ इस बात को रेखांकित करती हैं कि पश्चिम एशिया को एक समावेशी क्षेत्रीय सुरक्षा ढाँचे की आवश्यकता है। अब तक क्षेत्रीय सुरक्षा मुख्यतः बाहरी शक्तियों के सैन्य गठबंधनों और शक्ति संतुलन की राजनीति पर आधारित रही है किंतु इससे स्थायी शांति स्थापित नहीं हो सकी। इराक, यमन, सीरिया और फिलिस्तीन के उदाहरण बताते हैं कि संघर्षों के मूल कारण राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हैं, जिनका समाधान केवल सैन्य साधनों से संभव नहीं है। एक समावेशी सुरक्षा ढाँचा ऐसा होना चाहिए जिसमें खाड़ी सहयोग परिषद् (जीसीसी) के देश ईरान, इराक, तुर्किये, मिस्र तथा अन्य प्रमुख क्षेत्रीय ताकत समान रूप से भागीदारी करें। इसका उद्देश्य सामूहिक सुरक्षा, समुद्री मार्गों की रक्षा, आतंकवाद विरोधी सहयोग, ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा तथा विश्वास निर्माण होना चाहिए। यूरोप में शीतयुद्ध के बाद विकसित बहुपक्षीय सुरक्षा संस्थाओं की तरह पश्चिम एशिया को भी संवाद और सहयोग आधारित सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है। पश्चिम एशिया में समुद्री सुरक्षा का महत्व भी निरंतर बढ़ रहा है। हॉर्मुज जलडमरूमध्य और लाल सागर जैसे समुद्री मार्ग वैश्विक ऊर्जा और व्यापार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। हाल के वर्षों में इन क्षेत्रों में बढ़े तनाव ने यह स्पष्ट किया है कि क्षेत्रीय संघर्ष केवल संबंधित देशों तक सीमित नहीं रहते बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। तेल की कीमतों में वृद्धि, आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधा तथा व्यापारिक अनिश्चितता इसके प्रत्यक्ष परिणाम हैं। इसलिए किसी भी समावेशी सुरक्षा ढाँचे में समुद्री सुरक्षा को केंद्रीय स्थान देना आवश्यक है। भारत के लिए पश्चिम एशिया का महत्व बहुआयामी है। भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं का एक बड़ा भाग इसी क्षेत्र से पूरा होता है। सऊदी अरब, इराक, संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत जैसे देश भारत के प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ता हैं। यदि क्षेत्र में किसी प्रकार का सैन्य संघर्ष या समुद्री अवरोध उत्पन्न होता है तो उसका सीधा प्रभाव भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता पर पड़ता है। इसके अतिरिक्त लगभग 90 लाख भारतीय नागरिक विभिन्न खाड़ी देशों में कार्यरत हैं। ये प्रवासी भारतीय प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा भारत भेजते हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। किसी भी क्षेत्रीय संकट की स्थिति में उनकी सुरक्षा भारत के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता बन जाती है।

अंततः पश्चिम एशिया में हो रहे समकालीन भू-राजनीतिक परिवर्तन यह स्पष्ट करते हैं कि सैन्य हस्तक्षेपों पर आधारित सुरक्षा व्यवस्था अपनी सीमाओं तक पहुँच चुकी है। इराक, लीबिया, सीरिया और यमन के अनुभवों ने यह सिद्ध किया है कि स्थायी शांति केवल संवाद, समावेशन और क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से ही संभव है। खाड़ी देशों, ईरान और वैश्विक शक्तियों के बीच बदलते संबंध एक नई बहुध्रुवीय क्षेत्रीय व्यवस्था के निर्माण की ओर संकेत करते हैं। भारत के लिए यह अवसर और चुनौती दोनों है। यदि भारत अपनी विदेश नीति में रणनीतिक स्वायत्तता, ऊर्जा विविधीकरण, प्रवासी संरक्षण, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय सहयोग को प्राथमिकता देता है तो वह न केवल अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर सकेगा बल्कि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता का एक महत्वपूर्ण भागीदार भी बन सकेगा।

-यह लेखक के अपने विचार हैं।

महत्वपूर्ण निर्णय लेने में हमेशा फिसड्डी साबित होती राहुल की कांग्रेस

श्रीगोपाल नारसन
स्तंभकार

उत्तराखंड कांग्रेस में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की नई कार्यकारिणी के गठन को लेकर कार्यकर्ताओं का इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है। कई बार जल्द घोषणा के संकेत मिलने के बावजूद अब तक हाईकमान की अंतिम मंजूरी नहीं मिल सकी है। वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल पुरानी टीम के साथ संगठन का काम चला कर रहे हैं।

प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने देहरादून पहुंचने पर स्पष्ट किया था कि राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे के बाद नई पीसीसी कार्यकारिणी की घोषणा की जाएगी।लेकिन राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा खराब मौसम के चलते रद्द हो गया ,हालांकि उन्होंने वर्चुअल सम्बोधन कर कार्यकर्ताओ का मनोबल बढ़ाने की कोशिश की।प्रदेश प्रभारी शैलजा ने कहा कि कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह जुटी हुई है और संगठन को मजबूत बनाने के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व सक्रिय भूमिका निभा रहा है।

कांग्रेस हाईकमान प्रदेश संगठन की छोटी और प्रभावी टीम बनाकर नेताओं की जिम्मेदारियां तय करना चाहता है। हालांकि, वरिष्ठ नेताओं द्वारा अपने समर्थकों के नामों की लंबी सूची भेजे जाने के कारण कार्यकारिणी के गठन पर अंतिम फैसला अभी तक नहीं हो पाया है।कुमारी सैलजा ने कहा कि राहुल गांधी का वर्चुअल भाषण कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार कर गया है। विधानसभा और लोकसभा चुनावों में लगातार हार के बाद कांग्रेस को उम्मीद है कि राष्ट्रीय नेतृत्व की सक्रियता से संगठन को मजबूती मिलेगी।प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को आमंत्रित तो किया जा रहा है, लेकिन व्यवस्थाओं के मामले में सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई है। उन्होंने दावा किया कि जनता इस बार सरकार को जवाब देगी।

प्रदेश नेतृत्व का मानना है कि राहुल के उदबोधन से संगठन को नई दिशा मिली है और 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी को मजबूती प्राप्त हुई।लेकिन सवाल यह उठता है कि कांग्रेस समय से क्यो नही अपने निर्णय ले पाती।चाहे चुनाव में टिकट देने का मामला हो या फिर कार्यकारिणी गठन का मुद्दा कांग्रेस निर्णय लेने में ज्यादातर देरी ही करती है।साथ ही जमीन से जुड़े निष्ठावान कार्यकर्ताओ के बजाए अवसरवादी आगे आकर कांग्रेस के चुनाव परिणामों को गुड़ गोबर कर देते है।प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल के सामने कांग्रेस की मौजूद चुनोतियाँ साफ दिखती है, गुटों में बंटी कांग्रेस इकाई का नेतृत्व करना, वह भी 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले बेहद कठिन कहा जा सकता है।वह भी तब जब कांग्रेस पार्टी सन 2017 और सन 2022 के दो विधानसभा चुनाव हार चुकी हो, साथ ही राज्य की लगातार तीन लोकसभा चुनावों में भी एक भी सीट कांग्रेस नहीं जीत पाई है,जो पार्टी की कमजोर हालत को प्रमाणित करता है।दो बार के विधायक गणेश गोदियाल, जिन्हें कभी हरीश रावत का करीबी माना जाता था,का पुनः पदारूढ़ होने से उम्मीद है कि वे हरीश रावत को अपने से भी आगे करके चलेंगे। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले वह राज्य में कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके है, लेकिन उनके चुनाव हारने के बाद उनकी जगह करन माहरा को दे दी गई,परन्तु कांग्रेस कोई चमत्कार नही कर पाई।

हरीश रावत ने स्वयं को पीछे करते हुए सार्वजनिक रूप से सुझाव दिया था कि अगला विधानसभा चुनाव कांग्रेस को प्रीतम सिंह (जो पांच बार के विधायक हैं) के नेतृत्व में लड़ना चाहिए। उनका यह बयान पार्टी में एकता का पहला कदम कहा जा सकता है।जब कांग्रेस उत्तराखंड में सत्ता में थी, तब भी हरीश रावत लगातार संघर्षों में फंसे रहे, पहले एन.डी. तिवारी को उनका हक दे दिया गया,जिससे टकराव की स्तिथि बनी रही और बाद में मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा को बनाकर फिर से हरीश रावत को किनारे करने की कोशिश की गई।लेकिन प्राकृतिक आपदा में विजय बहुगुणा के फेल हो जाने के कारण उनकी जगह सन 2014 में हरीश रावत को मुख्यमंत्री पद पर रिप्लेस किया गया।यह बदलाव उस समय आया जब विजय बहुगुणा पर जून 2013 की केदारनाथ आपदा से निपटने को लेकर भारी आलोचना हो रही थी क्योंकि आपदा के समय विजय उत्तराखंड के बजाए दिल्ली में डेरा डाले हुए थे। पिछले दिनों करन माहरा को सीडब्ल्यूसी और प्रीतम सिंह को सीईसी में शामिल किया जाना, कांग्रेस हाईकमान द्वारा राज्य में प्रतिस्पर्धी गुटों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है, इसे हरीश रावत को उनकी नाखुशी के बावजूद केंद्रीय नेतृत्व से जोड़कर रखने की रणनीति भी माना जा रहा है।अपनी बढ़ती उम्र में भी बेहद सक्रिय कांग्रेस के शीर्ष नेता हरीश रावत के पास वर्तमान में कोई ठोस दायित्व नही है,फिर भी वे राज्य के सर्वाधिक सक्रिय नेता कहे जा सकते है।ऐसे में उनकी अनदेखी करके कांग्रेस कोई भी चुनाव फिलहाल नही लड़ सकती और यदि ऐसा हुआ तो फिर से कांग्रेस की लुटिया डूबने में देर नही लगेगी।पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा भी है कि वे पार्टी के लिए बूथ अध्यक्ष तक बनने को तैयार है। कांग्रेस ही नही अन्य राजनीतिक दलों को भी उत्तराखंड के इस सर्वमान्य नेता का सम्मान करना चाहिए।

-यह लेखक के अपने विचार हैं।

हेल्थ अपडेट

हर ओवेरियन सिस्ट कैंसर नहीं होती, डॉक्टर की सलाह से ही दूर होंगे मिथक

भारत सहित पूरी दुनिया की महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर के बाद ओवेरियन कैंसर का जोखिम सबसे अधिक होता है। ओवेरियन कैंसर महिलाओं की ओवरी यानी अंडाशय से शुरू होता है। यह अंग महिलाओं के प्रजनन अंग का ही हिस्सा होता है। अगर इस कैंसर की पहचान सही समय पर न की जाए तो यह जीवन के लिए घातक साबित हो सकता है। आज भी भारत की कई महिलाएं ओवरी यानी अंडाशय से जुड़ी कई स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में जागरूकता नहीं हैं। उनके बीच में ओवेरियन कैंसर से जुड़े कई मिथक आज भी प्रचलित हैं और उनको ही सच मान लिया जाता है।

महिलाओं के बीच अवधारणा है कि एचपीवी टेस्ट से ओवेरियन कैंसर का पता चलता है। जबकि एचपीवी और Pap Smear मुख्य रूप से सर्वाइकल (गर्भाशय ग्रीवा) कैंसर की जांच की जाती है। सीडीसी के अनुसार वर्तमान में ऐसा कोई नियमित स्क्रीनिंग टेस्ट उपलब्ध नहीं है जो सामान्य जोखिम वाली महिलाओं में शुरुआती अवस्था के ओवेरियन कैंसर का विश्वसनीय रूप से पता लगा सके।

ओवेरियन कैंसर मिथक : अल्ट्रासाउंड और सीए 125 टेस्ट महत्वपूर्ण टेस्ट हैं, लेकिन, इनमें से कोई भी जांच अकेले ओवेरियन कैंसर की निश्चित पुष्टि नहीं करते हैं। सीए 125 कई गैर कैंसर स्थितियों जैसे एंडोमेट्रियोसिस, संक्रमण, पीरियड्स और ओवेरियन कैंसर में भी बढ़ सकता है। जबकि, कुछ महिलाओं में कैंसर होने के बावजूद सीए 125 नॉर्मल रह सकता है। सीडीसी के अनुसार अल्ट्रासाउंड ओवरी में सिस्ट की पहचान कर सकता है, लेकिन यह नहीं बता सकता है कि यह सिस्ट या गांठ कैंसर का ही रूप है। कैंसर की अंतिम जांच बायोप्सी और पैथोलॉजी टेस्ट से ही होती है।

यह धारणा भी गलत है। अधिकांश ओवेरियन सिस्ट सामान्य और गैर-कैंसरयुक्त होती हैं। कई सिस्ट बिना किसी इलाज के अपने आप समाप्त हो जाती हैं। डॉक्टर सिस्ट का आकार, स्वरूप, महिला की उम्र, लक्षण और अन्य जांच रिपोर्टों को देखकर निर्णय लेते हैं कि सर्जरी आवश्यक है या नहीं। हर सिस्ट कैंसर में नहीं बदलती है। ओवेरियन कैंसर के बारे में गलत जानकारियां महिलाओं को भ्रमित कर सकती हैं। सही जानकारी और समय पर चिकित्सकीय सलाह ही इस बीमारी से बचाव और बेहतर परिणाम का सबसे प्रभावी तरीका है।

निशाना

तपता है मन जेठ सरीखा..!

बसंत शर्मा

स्वच्छ-सरल मन दे दो मुझको।
फिर से बचपन दे दो हमको।
तपता है मन जेठ सरीखा,
रिमझिम सावन दे दो मुझको।
गगन चूमते फ्लैट रखो तुम,
झूला आँगन दे दो मुझको।
हर पल आए काम किसी के,
ऐसा जीवन दे दो मुझको।
दे दो गाँवों की खुशहाली,
हरे-भरे वन दे दो मुझको।
केवल उसकी खातिर धड़के,
ऐसी धड़कन दे दो मुझको।
दिल्ली-विल्ली सब ले लो तुम,
बस वृन्दावन दे दो मुझको।

स्कैम अलर्ट

फ्री एलईडी बल्ब देने के बहाने घर आ रहे ठग, पीड़ित के नाम पर हो जाता है लोन

गांव-देहात में लोगों के साथ बड़ा फ्रॉड हो रहा है। जाने-माने इम्फ्लूएंसर वर्दीवाला ने लोगों को आगाह किया है। उनके अनुसार, फ्रॉड करने वाले लोगों के घर में फ्री एलईडी बल्ब देने के बहाने आते हैं। उनसे आधार कार्ड डिटेल्स और ओटीपी मांगते हैं। इसके बाद पीड़ित के नाम पर लोन करवा लिया जाता है। वर्दीवाला ने लोगों को सुरक्षित रहने का तरीका भी बताया है।

पहले भी ऐसे केस आए हैं और अब एक बार फिर से मासूम लोगों को ठगा जा रहा है। जाने-माने वर्दीवाला के अनुसार 4 से 5 लोग घर पर आकर बोलते हैं कि सरकारी स्कीम से आपको एलईडी बल्ब फ्री में दिए जा रहे हैं या कई बार कुछ पैसे जैसे- 10 रुपये मांगे जाते हैं। जो लोग भरोसा करते हैं, उनके साथ फ्रॉड का खतरा बढ़ जाता है।

वर्दीवाला के अनुसार, फ्री एलईडी बल्ब देने के नाम पर आधार कार्ड की मांग की जाती है। जैसे ही व्यक्ति अपना आधार कार्ड देता है, उसे मोबाइल पर आया ओटीपी बताने को कहा जाता है। ओटीपी देने के बाद आरोपी लोगों के आधार कार्ड पेमेंट इनेबल सिस्टम से लोन करवा सकते हैं। वो आपके नाम पर पैसे लेकर रफूचक्कर हो सकते हैं। सलाह है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ अपना आधार कार्ड शेयर ना करें जो कुछ फ्री में या बहुत कम पैसों में चीज देने के बदले आपसे आधार ओटीपी मांगे। व्यक्ति को आधार कार्ड देने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि वह आधिकारी पर्सन हो जैसे- कोई सरकारी कर्मचारी या बैंक कर्मी आदि।

अगर किसी परिस्थिति में आधार कार्ड देना भी पड़े तो मास्क्ड आधार कार्ड ही दें। इससे आधार कार्ड के नाम से आपके साथ किसी भी तरीके का फ्रॉड नहीं होगा। मास्क्ड आधार कार्ड ऑनलाइन जनरेट हो जाता है। किसी के साथ किसी भी तरीके का कोई फाइनेंशियल फ्रॉड होता है, तो तुरंत 1930 पर कॉल कर पुलिस को इसकी सूचना दें।

पहले भी सामने आए मामले: Free LED बल्ब देने के बदले आधार कार्ड डिटेल और उस पर आने वाले ओटीपी मांगने के मामले पहले भी सामने आए हैं। भोले भाले लोग झांसे में आ जाते हैं और सस्ते बल्ब के चक्कर में अपनी गोपनीय जानकारी शेयर कर देते हैं। सरकार ऐसी धोखाधड़ी को लेकर चेतावनी जारी कर चुकी है। आप इस जानकारी को अपने परिवार और करीबियों तक भी साझा करें जिससे अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किया जा सके। याद रहे कि आधार कार्ड के साथ आप बैंक अकाउंट नंबर जुड़ा होता है। ऐसे में थोड़ी सी भी लापरवाही आपको फ्रॉड का शिकार बना सकती है।

वायरल कंटेंट

पैसे गिनने का देसी जुगाड़ हुआ वायरल नोट संभालने की ट्रिक देख लोग हैरान

सोशल मीडिया पर रोजाना कोई ना कोई ऐसा वीडियो वायरल हो जाता है, जो लोगों को या तो हैरान कर देता है या फिर हंसने पर मजबूर कर देता है। कभी लोग घर के काम आसान करने के जुगाड़ दिखाते हैं तो कभी ऐसे हैक्स सामने आते हैं, जिन्हें देखकर लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इसकी जरूरत क्या थी। इन दिनों इंटरनेट पर एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स नोट गिनने का बेहद अलग और देसी तरीका दिखाता नजर आ रहा है। वीडियो देखने के बाद कुछ लोग इस ट्रिक को शानदार बता रहे हैं, जबकि कई यूजर्स इसे सिर्फ समय की बर्बादी कह रहे हैं। यही वजह है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का बड़ा विषय बन चुका है।

वायरल हो रहे है वीडियो में दिखता है कि एक शख्स 500 रुपये के नोटों की मोटी गड्डी अपने हाथ में पकड़ता है। इसके बाद वह गड्डी में से एक नोट निकालकर उसे खास अंदाज में मोड़ देता है। फिर वह अपने अंगूठे और उंगलियों की मदद से बाकी नोटों को धीरे-धीरे आगे की तरफ सरकाता है और उन्हें सही तरीके से उसमें लगाने लगता है। कुछ ही सेकंड में पूरी गड्डी एक अलग स्टाइल में सेट हो जाती है। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि इस तरीके से नोट जल्दी-जल्दी अलग हो जाते हैं और उन्हें गिनना आसान हो जाता है। इसके बाद शख्स नोटों को एक-एक करके तेजी से निकालकर गिनता हुआ नजर आता है।

लोगों ने दिए मजेदार रिएक्शन: इस वीडियो को @Viranshi_Yadav_ नाम के एक्स अकाउंट पर शेयर किया गया है। इसे 4 लाख से ज्यादा लोगों ने देख लिया है। वीडियो वायरल होते ही लोगों ने कमेंट सेक्शन में मजेदार प्रतिक्रियाओं की बाढ़ ला दी। कुछ लोगों को यह ट्रिक काफी दिलचस्प लगी, तो कुछ यूजर्स ने इसे देखकर मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। एक यूजर ने लिखा- 'भाई, इतने रुपये होने तो चाहिए गिनने के लिए।' वहीं दूसरे यूजर ने मजाक करते हुए कहा- 'इतनी देर में तो पूरे पैसे दो बार गिन जाते।' एक और यूजर ने लिखा- 'गिनने में आसानी हो सकती है, लेकिन वापस समेटने में ज्यादा समय लग जाएगा.' जहां कुछ यूजर्स इस देसी जुगाड़ की तारीफ कर रहे थे, वहीं कई लोगों को यह तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया। एक यूजर ने लिखा- 'जितनी देर में ये फोल्ड बनेंगे, उतनी देर में मैं दो बार पैसे गिन चुका होता।' दूसरे यूजर ने लिखा- 'इतनी देर में हम 6 बार पैसे गिन लेते और 10 बार निकाल भी लेते।' वहीं एक अन्य यूजर ने मजाकिया अंदाज में कहा- 'इतना रायता फैलाने की आखिर जरूरत क्या थी?'

न्यूज विंडो

पार्किंग क्षेत्र से बाहर भी वसूली नगर परिषद के ठेके पर सवाल

अमरकंटक। नगर परिषद अमरकंटक द्वारा वाहन पार्किंग वसूली का ठेका दिए जाने के बाद अब पार्किंग शुल्क वसूली को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ठेकेदार द्वारा निर्धारित पार्किंग क्षेत्र के बाहर भी वाहन चालकों से शुल्क वसूला जा रहा है, जबकि ठेका अनुबंध में स्पष्ट रूप से केवल चिह्नित पार्किंग क्षेत्र में खड़े वाहनों से ही शुल्क लेने का प्रावधान बताया गया है। जानकारी के अनुसार नगर परिषद अमरकंटक ने वाहन पार्किंग वसूली कार्य के लिए निविदा जारी कर ठेका प्रदान किया है। टेंडर का उद्देश्य निर्धारित पार्किंग स्थलों का संचालन एवं शुल्क संग्रहण है। यदि वाहन पार्किंग स्थल के बाहर सड़क किनारे या सार्वजनिक स्थान पर खड़ा है तो उससे पार्किंग शुल्क लेना नियमों के विपरीत माना जा सकता है। नगर निकाय द्वारा दिए गए अनुबंध की शर्तों का पालन कराना परिषद प्रशासन की जिम्मेदारी है। नगर परिषद एवं नगरीय प्रशासन विभाग के नियमों के अनुसार ठेकेदार केवल उन्हीं क्षेत्रों में शुल्क वसूल सकता है जो अनुबंध अथवा परिषद द्वारा अधिकृत किए गए हों।

संजीव रघुवंशी बने भोपाल संभाग के कार्यकारी अध्यक्ष

गंज बासौदा। मध्यप्रदेश शासकीय शिक्षक संगठन के प्रदेशाध्यक्ष राकेश दुबे एवं प्रदेश महामंत्री उमेश सोनी की अनुशंसा पर प्रदेश उपाध्यक्ष पृथ्वी सिंह रघुवंशी तथा नबल सिंह रघुवंशी के प्रस्ताव के आधार पर संभाग अध्यक्ष कमल बैरागी ने माध्यमिक शाला चौरावर, बासौदा के शिक्षक संजीव रघुवंशी को भोपाल संभाग का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। प्रदेश उपाध्यक्ष पृथ्वी सिंह रघुवंशी ने कहा कि संजीव रघुवंशी सदैव शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए आगे रहे हैं। वे एक मिलनसार एवं सक्रिय व्यक्तित्व के धनी हैं तथा शिक्षक हितों के लिए निरंतर कार्य करते रहे हैं।

संजीव रघुवंशी की नियुक्ति पर संभाग एवं जिले के शिक्षकों में हर्ष व्याप्त है। शिक्षकों ने उन्हें बधाई देते हुए संगठन को और अधिक मजबूत बनाने की शुभकामनाएं दीं। बधाई देने वालों में अमर सिंह तोमर, नीलम रघुवंशी, विनोद श्रीवास्तव, जितेंद्र नामदेव, सफाकत हुसैन कादरी, लम्पूराम अहिरवार, महेंद्र सिंह, निर्भय सिंह, राहुल शर्मा, अरुण पांडे, काशीराम मालवीय, अभिषेक माथुर, अजय शर्मा, रामराज सिंह दांगी, दीपक नामदेव, ज्ञान सिंह लोधी, संजय अहिरवार, संजय विश्वकर्मा, कृपाराम सैन, पूरन सिंह लोधी, माधवी भाटिया, अनीता ठाकुर, सपना शर्मा, रितु सिंह, तृप्ति तिवारी, रश्मि राजपूत, सरिता ठाकुर, प्रेमिला रघुवंशी, सरस्वती सैन, अनीता साहू, ममता छावड़ा, भारती शर्मा, मुक्ता श्रीवास्तव सहित अनेक शिक्षक शामिल रहे।

नरसिंहपुर में ऑपरेशन ईगल क्लॉ' के तहत पुलिस ने पकड़ा गांजा तस्कर

नरसिंहपुर। जिले में मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान 'ऑपरेशन ईगल क्लॉ' के तहत पुलिस ने एक युवक को करीब 1.5 किलोग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की अनुमानित कीमत 30 हजार रुपये बताई गई है।

जंग लगे खंभों से टूटकर हवा में झूल रहे सिग्नल बॉक्स, राहगीरों के लिए खतरा

शहडोल। शहर में बढ़ती आबादी और सड़कों पर लगातार बढ़ रहे वाहनों के दबाव के बीच शहडोल की यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई नजर आ रही है। लाखों रुपये खर्च कर लगाए गए ट्रैफिक सिग्नल अब बदहाली का शिकार हो चुके हैं। कई प्रमुख चौराहों पर सिग्नलों की भारी-भरकम लाइटें जंग लगे खंभों से टूटकर हवा में झूल रही हैं, जिससे हर समय दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। तेज रफ्तार ट्रैफिक के बीच इन लटके सिग्नलों के नीचे से गुजरने वाले राहगीर और दोपहिया वाहन चालक डर के साये में सफर करने को मजबूर हैं। शहर के नया गांधी चौक, इंदिरा चौक, अंबेडकर चौक और जयस्तंभ चौक जैसे व्यस्त चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल बंद पड़े होने से यातायात व्यवस्था पूरी तरह अव्यवस्थित हो गई है। सिग्नलों के काम नहीं करने से चारों दिशाओं से वाहन एक साथ चौराहे पर पहुंच जाते हैं, जिसके कारण दिन में कई बार जाम की स्थिति बन रही है। वाहन चालकों के बीच पहले निकलने की होड़ में विवाद, बहस और गाली-गलौज की घटनाएं आम हो गई हैं, वहीं दुर्घटनाओं का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। जानकारी के अनुसार वर्ष 2016 में शहर को आधुनिक यातायात व्यवस्था देने के उद्देश्य से इन प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए थे। साथ ही डिवाइडरों के बीच खतरनाक क्रॉसिंग प्वाइंट्स पर अलर्ट ब्लिंकर्स भी लगाए गए थे, ताकि वाहन चालकों और राहगीरों को सतर्क किया जा सके। नगर पालिका द्वारा ठेका प्राप्त कंपनी को पांच वर्षों के मेंटेनेंस का कार्य सौंपा गया था।

निर्माण की गुणवत्ता और संरचना की स्थिरता को लेकर बढ़ी लोगों की चिंता

एनएच-46 बरखेड़ा अंडरपास की रिटेनिंग वॉल पर उठे सवाल, सहारे के लिए लगाए भारी बैग

औबेदुल्लागंज। दोपहर मेट्रो

औबेदुल्लागंज से निकलकर भोपाल को नागपुर से जोड़ने बाले व्यस्ततम राष्ट्रीय राजमार्ग-46 पर बरखेड़ा के समीप निर्मित अंडरपास एवं उससे जुड़ी रिटेनिंग वॉल की स्थिति को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। मौके पर दीवार के सहारे बड़ी संख्या में भारी भरकम बैग रखे गए हैं, जबकि कई स्थानों पर प्रीकास्ट कंक्रीट पैनलों के जोड़ असमान दिखाई दे रहे हैं। इससे स्थानीय लोगों में निर्माण की गुणवत्ता और संरचना की स्थिरता को लेकर चिंता बढ़ गई है। स्थल पर देखने से प्रतीत होता है कि रिटेनिंग वॉल के सामने पूरी लंबाई में भारी बैग रखे गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि सामान्य परिस्थितियों में ऐसी संरचनाओं के सामने इस प्रकार का अतिरिक्त भार नहीं रखा जाता। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि यह व्यवस्था नियमित निर्माण प्रक्रिया का हिस्सा है या किसी तकनीकी समस्या के बाद की गई अस्थायी सुरक्षा व्यवस्था। निरीक्षण के दौरान कुछ स्थानों पर पैनलों के बीच गैप असमान दिखाई दिए, वहीं कुछ हिस्सों में पानी के रिसाव के निशान भी नजर आए। अंडरपास के समीप दीवार और ऊपरी संरचना के जंक्शन पर भी पैचवर्क और विकृति जैसे संकेत दिखाई देते हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं।

संबंधित विभाग मामले में स्थिति स्पष्ट करे

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि संरचना पूरी तरह सुरक्षित है तो उसके सहारे भारी बैग रखने की आवश्यकता क्यों पड़ी। वहीं यदि किसी प्रकार की तकनीकी समस्या सामने आई है तो उसकी आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए। मामले को लेकर अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या संबंधित निर्माण एजेंसी एवं एमपीआरडीसी द्वारा संरचना की तकनीकी जांच कराई गई है? यदि जांच हुई है तो उसकी रिपोर्ट क्या कहती है? साथ ही क्या रिटेनिंग वॉल की स्थिरता, धंसाव और जल निकासी व्यवस्था का स्वतंत्र परीक्षण कराया गया है? जनहित को देखते हुए स्थानीय नागरिकों ने मांग की है कि संबंधित विभाग इस मामले में स्थिति स्पष्ट करे तथा आवश्यकता होने पर स्वतंत्र तकनीकी ऑडिट कराकर उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करे, ताकि भविष्य में किसी संभावित दुर्घटना की आशंका को समय रहते टाला जा सके।

पचमढ़ी मार्ग में चलती कार पर दो बाघों ने किया अटैक, सड़क पर घूम रहे 6 टाइगर

नर्मदापुरम। दोपहर मेट्रो

जिले के अंतर्गत आने वाले हिल स्टेशन पचमढ़ी जाने वाले रास्ते पर ग्राम झिरिया से मटकुली तक 6 टाइगर सड़क के आसपास घूम रहे हैं। बीती देर रात करीब 2 बजे दो बाघों ने एक चलती कार पर हमला कर दिया। कार के शीशे पर पंजा मार दिया। यही नहीं, दोनों टाइगर कार के पीछे भी भागने लगे। कार चालक ने किसी तरह तेज रफ्तार कर अपनी जान बचाई। इसी तरह एक बाइक सवार दंपति पर भी टाइगर ने हमला किया। बाइक और कार सवारों ने किसी तरह जान बचाई और फारेस्ट के चैकपोस्ट पर पहुंचे।

जिले के पिपरिया में रहने वाले सुजीत पटवा ने बताया कि, देर रात वो नागपुर से पिपरिया की तरफ आ रहे थे। इसी दौरान डोकरीखेड़ा से झिरिया के बीच रास्ते मे पहले एक टाइगर ने चलती कार पर हमले का प्रयास किया। इसी बीच माइल स्टोन के पास छिपकर बैठे एक दूसरे टाइगर ने हमला कर दिया। किसी तरह जान बचाकर पहुंचे पटवा ने चैकपोस्ट पर कर्मचारियों को घटना की जानकारी दी। चैक पोस्ट पर पहले से खड़े बाइक सवार दंपति ने बताया कि, उन पर भी बाघ ने हमला किया था।

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के मुताबिक, जिस इलाके में बाघ के हमले की जानकारी मिली है। वो सामान्य रूप से वन क्षेत्र में आता है। इसके बाद दिन में भी लोग सड़क मार्ग से पचमढ़ी, मटकुली की तरफ जाने से कतराने लगे हैं। वन विभाग और एसटीआर ने जंगल गश्ती दलों को सतर्क कर दिया है। राहगीरों के सतर्क रह कर रात के समय अकेले मार्ग से निकलने में परहेज करने की सलाह दी जा रही है। घटना के बाद से राहगीरों में दहशत बन गई है। इस मार्ग से लोग दिन में भी गुजरने से डरने लगे हैं। कार सवार पटवा ने बताया कि, घटना की जानकारी देने के बाद मैं काफी देर नाके पर ही खड़ा रहा। इस दौरान मटकुली, झिरिया की तरफ जाने वाले बाइक सवारों को रोक लिया। कुछ बस चालकों को भी रास्ते में टाइगर होने की जानकारी दी थी।

क्रांतिकारी किसान संगठन के पदाधिकारी पर मीडियाकर्मी से मारपीट का आरोप, केस दर्ज

नर्मदापुरम/इटारसी। दोपहर मेट्रो

इटारसी में समाचार प्रकाशित होने को लेकर शुरू हुआ विवाद मारपीट तक पहुंच गया। क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन के यूथ विंग प्रदेशाध्यक्ष अरुण पटेल पर अधिमान्य पत्रकार राकेश पटेल से मारपीट करने का आरोप लगा है। वहीं, अरुण पटेल ने भी पत्रकार पर घर में घुसकर गाली-गलौज और मारपीट करने का आरोप लगाया है। मामले में इटारसी पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर काउंटर केस दर्ज किया है।

जानकारी के अनुसार, पत्रकार राकेश पटेल विभिन्न न्यूज चैनलों और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए कार्य करते हैं। विवाद की शुरुआत सोशल मीडिया पर की गई एक पोस्ट से हुई। आरोप है कि अरुण पटेल ने एक व्हाट्सएप ग्रुप में राकेश पटेल की खबर को लेकर आपत्तिजनक और अमर्यादित टिप्पणी की थी। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 7:30 बजे राकेश पटेल ने अरुण पटेल को फोन कर व्हाट्सएप ग्रुप में की गई पोस्ट के संबंध में बात की। इस दौरान अरुण ने उन्हें घर बुलाकर आमने-सामने चर्चा करने के लिए कहा। राकेश पटेल का आरोप है कि जब वे अरुण पटेल के घर पहुंचे तो वहां उनके साथ गाली-गलौज की गई। विरोध करने पर अरुण पटेल, उनकी पत्नी राधिका और एक अन्य व्यक्ति ने उन्हें पकड़ लिया और क्रिकेट के बल्ले से सिर, हाथ, जांघ, कमर और सीने पर हमला किया। साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी गई।

घायल पत्रकार को उपचार के लिए इटारसी के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि सिटी स्कैन में सिर में अंदरूनी चोट के संकेत मिले हैं। वहीं, अरुण पटेल ने अपने आरोपों में कहा है कि पत्रकार द्वारा कई बार समाचारों में बदलाव किया जाता था और संगठन से जुड़े नाम व फोटो प्रकाशित नहीं किए जाते थे। उन्होंने दावा किया कि शुक्रवार सुबह राकेश पटेल स्वयं उनके घर पहुंचे और अपशब्द कहते हुए विवाद शुरू किया।

इटारसी थाना प्रभारी सौरभ पांडे ने बताया कि दोनों पक्षों की शिकायत प्राप्त हुई है और दोनों की रिपोर्ट पर काउंटर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। सूत्रों के अनुसार, अरुण पटेल ने अपने चौरिया जन जागृति एकता नामक व्हाट्सएप ग्रुप में देर रात एक पोस्ट साझा कर पत्रकार राकेश पटेल के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया था। हालांकि, इस पहलू को लेकर पुलिस द्वारा फिलहाल अतिरिक्त धाराएं नहीं जोड़ी गई हैं।

कोरोनाकाल के बाद अब तक बंद ट्रेन शुरू नहीं गुस्साए यात्रियों ने आंदोलन की दी चेतावनी

औबेदुल्लागंज। दोपहर मेट्रो

कोरोना काल में अस्थायी रूप से बंद किए गए ट्रेनों के ठहराव को बहाल न किए जाने से बरखेड़ा क्षेत्र के हजारों यात्रियों की परेशानी अब जनआक्रोश में बदलने लगी है। वर्षों बीत जाने के बाद भी राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित बरखेड़ा रेलवे स्टेशन पर महत्वपूर्ण यात्री ट्रेनों का स्टॉपेज शुरू नहीं हो सका है, जिससे ग्रामीणों में रेलवे प्रशासन के प्रति नाराजगी बढ़ रही है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि कोरोना महामारी समाप्त हुए लंबा समय गुजर चुका है, लेकिन इंदौर-छिंदवाड़ा पंचवैली फास्ट पैसेंजर और झांसी-इटारसी पैसेंजर जैसी ट्रेनों का ठहराव अब तक बहाल नहीं किया गया। इसका सीधा असर विद्यार्थियों, मजदूरों, व्यापारियों, बुजुर्गों और मरीजों पर पड़ रहा है, जिन्हें छोटे-छोटे कामों के लिए भी दूसरे स्टेशनों का सहारा लेना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि बरखेड़ा जैसे महत्वपूर्ण स्टेशन की लगातार अनदेखी की जा रही है, जबकि यहां से प्रतिदिन बड़ी

संख्या में लोग यात्रा करते हैं। रेलवे की इस उदासीनता के खिलाफ अब लोगों ने संगठित होकर आवाज उठानी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में ग्रामीणों ने स्टेशन मास्टर को ज्ञापन सौंपकर ट्रेनों का ठहराव तत्काल बहाल करने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि 15 दिनों के भीतर सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो क्षेत्रवासी आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। ग्रामीणों का कहना है कि यह केवल ट्रेनों के ठहराव का मुद्दा नहीं, बल्कि क्षेत्र की मूलभूत यातायात सुविधा और आम नागरिकों की जरूरतों से जुड़ा विषय है। यदि रेलवे प्रशासन ने समय रहते समाधान नहीं निकाला तो आने वाले दिनों में विरोध प्रदर्शन और तेज हो सकता है। ज्ञापन सौंपने वालों में दिनेश अग्रवाल, भगवान सिंह चौहान, संजय शर्मा, शंकर लाल प्रजापति, पंकज गुप्ता, गुलफाम खान, इदरीश खान, हयात मोहम्मद सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

विधायक ने किया ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा

बुजुर्गों व युवाओं से संवाद समस्याओं का लिया जायजा

सिरोंज। दोपहर मेट्रो

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे विशेष जनसंपर्क अभियान के अंतर्गत क्षेत्रीय विधायक उमाकांत शर्मा ने शुक्रवार को विधानसभा अंतर्गत आने वाले खेजड़ा हाली, टाडा बंजारा तहसील सिरोंज एवं , सतपाड़ा , आनंदपुर एवं जावती तहसील लटेरी के ग्रामों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों एवं बुजुर्गजनों का सम्मान कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया तथा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वस्थ, दीर्घ एवं यशस्वी जीवन की कामना की, वहीं उन्होंने युवाओं से संवाद भी किया जिसमें युवाओं ने मोदी जी के द्वारा राष्ट्र हित मे किये जा रहे हैं कार्यों की सराहना की। विशेष जनसंपर्क अभियान के दौरान विधायक शर्मा ने विभिन्न ग्रामों में स्वच्छता अभियान एवं प्रगति पथ यात्रा सहित अनेक कार्यक्रमों में सहभागिता की। उन्होंने ग्रामीणों, प्रबुद्धजनों एवं भाजपा कार्यकर्ताओं से आत्मीय संवाद करते हुए केंद्र एवं प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी साझा की।

विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में भारत ने विकास, सुशासन, गरीब कल्याण एवं आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। आज देश वैश्विक मंच पर नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है और शासन की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प साकार होने की दिशा में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है।

दौरे के दौरान विधायक शर्मा ने ग्रामों के वरिष्ठ नागरिकों एवं बुजुर्गजनों का सम्मान किया और उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी, स्वस्थ एवं दीर्घ जीवन के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया। बुजुर्गों ने प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा राष्ट्रहित में किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए उनके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना की।

विधायक शर्मा विभिन्न धार्मिक स्थलों पर भी पहुंचे, जहां उन्होंने क्षेत्र की सुख-समृद्धि, खुशहाली एवं निरंतर विकास के लिए स्थानीय देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं एवं सुझावों को गंभीरता से सुना तथा उनके निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केंद्र एवं प्रदेश की डबल इंजन सरकार के कारण विकास कार्यों को नई गति मिली है। सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आधारभूत संरचना के क्षेत्र में हुए कार्यों से ग्रामीण क्षेत्रों के जीवन स्तर में व्यापक सुधार आया है।

मेट्रो एंकर

अगस्त में शुरू होगी मध्यप्रदेश के अमरनाथ कहे जाने वाले नागद्वारी की यात्रा

नागद्वारी यात्रा की तैयारियां तेज, कलेक्टर ने पैदल ट्रैकिंग कर परखी व्यवस्थाएं

नर्मदापुरम। दोपहर मेट्रो

मध्यप्रदेश के अमरनाथ के नाम से प्रसिद्ध नागद्वारी गुफा की वार्षिक यात्रा अगस्त 2026 में प्रारंभ होगी। नाग पंचमी पर्व के अवसर पर आयोजित होने वाले इस प्रसिद्ध नागद्वारी मेले की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने अधिकारियों के साथ नागद्वारी मंदिर तक पैदल ट्रैकिंग कर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया।

निरीक्षण का उद्देश्य मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को सुरक्षित, सुगम और बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना रहा। कलेक्टर ने जलगली, नागफनी, कालाझाड़, चिंतामन, चित्रशाला, स्वर्गद्वार, पश्चिमद्वार, नागद्वारी मंदिर और काजरी सहित विभिन्न महत्वपूर्ण स्थलों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

इस दौरान उन्होंने पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं, सुरक्षा, विद्युत, स्वच्छता, मार्ग सुधार, संचार व्यवस्था और आपदा प्रबंधन संबंधी तैयारियों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं के आवागमन को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए ट्रैकिंग मार्गों का समय पर सुधार किया जाए और मेला क्षेत्र में सभी आवश्यक सुविधाएं तय समय सीमा में उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। निरीक्षण के दौरान विश्राम स्थलों, संकेतक बोर्डों और पर्यटक सुविधाओं की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि मेला क्षेत्र में स्वच्छता, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं और सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह सुदृढ़ किया जाए। कलेक्टर ने कहा कि नागद्वारी मेला प्रदेश के प्रमुख धार्मिक आयोजनों में से एक है, जिसमें मध्यप्रदेश सहित अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इसलिए सभी विभागों की जिम्मेदारी है कि वे बेहतर समन्वय के साथ श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराएं। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक साई कृष्ण एस. थोटा, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की उप संचालक ऋषभा नेताम, जिला पंचायत सीईओ एवं महादेव मेला समिति के अध्यक्ष हिमांशु जैन, एसडीएम पिपरिया आकिब खान, सहायक संचालक संजीव शर्मा, एसडीओपी मोहित यादव, तहसीलदार वैभव बैरागी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

बैतूल में 'विजय सेवा न्यास' द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल

42 परिवारों के 59 बेसहारा बच्चों के लिए फीस का चेक सौंपा

बैतूल/भोपाल। दोपहर मेट्रो

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व विधायक हेमंत खण्डेलवाल ने बैतूल के रामकृष्ण बगिया में 'विजय सेवा न्यास' द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 42 बेसहारा परिवारों के 59 बच्चों की स्कूल फीस चेक संबंधित विद्यालयों के संचालकों व प्राचार्यों को सौंपे। साथ ही शैक्षणिक सामग्री के लिए अलग से दो-दो हजार रूपए प्रति बच्चो दिए गए हैं।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष खण्डेलवाल ने बेसहारा परिवारों की देखभाल करने वाले उनके अभिभावकों को भी 20-20 हजार की आर्थिक सहायता देने के साथ शासकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बेसहारा बच्चों के परिजनों को भी 10-10 हजार की आर्थिक मदद की है। खण्डेलवाल ने कहा कि पूर्व सांसद स्वर्गीय विजय कुमार खंडेलवाल की स्मृति में संचालित किए जा रहे विजय सेवा न्याय द्वारा गोद लिए 59 बेसहारा बच्चों की पढ़ाई सहित उनके समग्र विकास की जिम्मेदारी खण्डेलवाल परिवार द्वारा निर्वहन की जा रही है। विजय सेवा न्यास बेसहारा बच्चों को शिक्षित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहा है। बेसहारा बच्चों की शिक्षा पूरी होने के बाद उनके रोजगार और स्वरोजगार की भी चिंता की जाएगी। राजनीति को सेवा का माध्यम बनाने वाले पूर्व सांसद स्वर्गीय विजय खण्डेलवाल के कार्यों को खण्डेलवाल परिवार आगे बढ़ा रहा है। कार्यक्रम को केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके, विधायक चंद्रशेखर देशमुख, महेन्द्र सिंह चौहान, प्रदेश प्रवक्ता व विधायक डॉ. योगेश पंडाग्रे एवं जिला अध्यक्ष सुधाकर पवार ने भी संबोधित किया।खण्डेलवाल ने कहा कि पूर्व सांसद स्वर्गीय विजय कुमार खण्डेलवाल ने राजनीति को सेवा का सशक्त माध्यम बनाया था। उनके देवलोकगमन के बाद खण्डेलवाल परिवार ने उनके दिखाए मार्ग पर चलकर सेवा कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए विजय सेवा न्यास की स्थापना की। विजय सेवा न्यास के जरिए बेसहारा बच्चों को शिक्षा का पूरा खर्च उठाया जा रहा है। इसके साथ ही बेसहारा बच्चों के परिवारों को भी आर्थिक मदद विजय सेवा न्यास द्वारा की जा रही है। उन्होंने कहा कि मानव सेवा ही माधव सेवा के मार्ग पर चलते हुए बेसहारा बच्चों को सहारा देने का कार्य विजय सेवा न्यास द्वारा कई वर्षों से किया जा रहा है। वर्ष 2025 में 41 बच्चों की फीस का पूरा खर्च विजय सेवा न्यास ने वहन किया था, इस साल बच्चों की संख्या बढ़कर 59 हो गई है। खण्डेलवाल ने परिवार द्वारा संचालित विजय सेवा न्यास के सेवा प्रकल्पों द्वारा किए जा रहे सामाजिक सरोकारों की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि विजय सेवा न्यास शिक्षा से रोजगार, चिकित्सा सहायता, महिला सशक्तिकरण, बेसहारा को सहारा देने के लिए कई प्रकल्प चलाए जा रहे हैं।

परिवार के सदस्य की तरह निभा रहे जिम्मेदारी

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खण्डेलवाल ने कहा कि पूर्व सांसद स्व. विजय कुमार खंडेलवाल के सेवा, संवेदना और समर्पण के संस्कार आज भी समाज को नई दिशा दे रहे हैं। उनके इसी प्रेरक जीवन दर्शन को आगे बढ़ाते हुए खण्डेलवाल परिवार ने विजय सेवा न्यास के माध्यम से बेसहारा बच्चों के जीवन में नई उम्मीद जगाने का अनुकरणीय अभियान शुरू किया है। बेसहारा बच्चों की परिवार के सदस्य की तरह शिक्षा और समग्र विकास की चिंता करते हुए जिम्मेदारी निभा रहे हैं। विजय सेवा न्यास के बेसहारा को सहारा प्रकल्प के अंतर्गत उन बच्चों को संरक्षण दिया जा रहा है उन्होंने कहा कि जिन बच्चों ने दुर्घटना में अपने माता-पिता या अभिभावकों को खो दिया है, वह खुद को बेसहारा न समझें। विजय सेवा न्यास ऐसे बच्चों के अभिभावक की कमी को पूरा नहीं कर सकता, लेकिन उनकी जिंदगी को संवारने का कार्य अवश्य करेगा।

परिवारों को भी आत्मनिर्भर बनाने का कर रहे प्रयास

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल ने कहा कि बेसहारा बच्चों को शिक्षा का पूरा खर्च वहन करने के साथ ही उनके अभिभावकों की भी आर्थिक मदद की जा रही है। इसके साथ ऐसे परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने में भी विजय सेवा न्यास विभिन्न प्रकल्पों के जरिए मदद पहुंचा रहा है। उन्होंने कहा कि केवल बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना भी जरूरी है। इसी सोच के तहत बच्चों की परवरिश कर रहे परिजनों को उनकी योग्यता और क्षमता के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बच्चों को उनकी मनपसंद विद्यालयों में सुविधा के अनुसार प्रवेश दिलाया गया है। बेसहारा बच्चों के जीवन में शिक्षा की रोशनी पहुंचाने के इस अभियान को समाज का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है।

न्यूज विंडो

एसपी से की प्रोजेक्ट डायरेक्टर पर केस दर्ज करने की मांग

नरसिंहपुर । एनएचएआई -44-छिंदवाड़ा बाईपास पर शासकीय सम्पति को नुकसान होने के कारण प्रोजेक्ट डायरेक्टर पर अधिनियम 1984 के तहत एफआईआर दर्ज की जाए। उक्त मांग भूतपूर्व जिला सैनिक संघ के अध्यक्ष लाल साहब जाट ने पुलिस अधीक्षक से की है। श्री जाट ने बताया कि पुलिस अधीक्षक पत्र देकर बताया है कि एनएचएआई -44 छिंदवाड़ा बाईपास ब्रिज के नीचे लाखों रुपए की लागत से गार्डन बनाया गया है। जिसमें माली के लिये मकान पौधों की सिंचाई के लिये ट्यूबवेल रोशनी के लिये बिजली की व्यवस्था की गई है। परंतु विगत एक वर्ष से अव्यवस्थता के चलते माली को बंद कर दिया. मकान तोड़ दिया, ट्यूबवेल से मोटर निकाल ली गई है। बिजली बंद कर दी गई। बाउंड्री वॉल क्षतिग्रस्त कर दी गई है। इस विभाग की लापरवाही के कारण यह नुकसान हो रहा है और शिकायत के बाद कार्रवाई नहीं की जा रही। अतः लगभग 50 लाख से बना यह स्थान अव्यवस्थित हो गया है। साथ ही आस-पास अतिक्रमण हो रहा जिसकी जानकारी विभाग को है। किंतु विभाग उदासीन बना है। वहीं ब्रिज के पास रोड से 50 मीटर की दूरी पर शरण ठेका खोलने की तैयारी चल रही है। जबकि एन एच ए आई रोड से 500 मीटर की दूरी आवश्यक है। किंतु यह सब विभाग की मिलीभगत से हो रहा है। ब्रिज के नीचे दोनों तरफ नालियां बनाई जा रही हैं। शासकीय सम्पति के प्रति लापरवाही उदासीनता देखते हुए जिम्मेदारों के खिलाफ अपराध दर्ज किया जाए । लालसाहब जाट ने बताया कि वे कलेक्टर और अन्य संबंधित उच्च अधिकारियों को भी शिकायत कर रहे हैं।

झूठी शिकायत या सच का खुलासा? भूमि विवाद की जांच की मांग तेज

तेंदूखेड़ा। ग्राम सेलवाड़ा, के निवासियो एवं ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों ने तहसीलदार, एसडीएम तथा कलेक्टर दमोह के नाम तहसीलदार विवेक व्यास को ज्ञापन सौंपकर जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक-7 सेलवाड़ा की वर्तमान बीडीसी सदस्य पूजा पति मलखान यादव के विरुद्ध जांच एवं कार्रवाई की मांग की है। आवेदनकर्ता कमलेश पिता रामसेवक साहू एवं सरपंच नीतू पति रमेश्वर साहू ने आरोप लगाया है कि उनके विरुद्ध सरकारी भूमि पर कब्जे संबंधी झूठी एवं तथ्यहीन शिकायत प्रस्तुत की गई है। उनका कहना है कि शिकायत में किसी भी शासकीय भूमि का खसरा नंबर, नक्शा, राजस्व अभिलेख अथवा अन्य प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि ग्राम सेलवाड़ा स्थित खसरा नंबर 974 (एस) एवं 962 (एस) राजस्व अभिलेखों के अनुसार निजी रैयती भूमि हैं। आवेदकों का दावा है कि खसरा नंबर 974 (एस) पर पिछले कई वर्षों से कथित रूप से अवैध कब्जा किया गया है, जिससे वास्तविक काश्तकार भूमि का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। वहीं खसरा नंबर 962 (एस) को भी राजस्व रिकॉर्ड में निजी भूमि बताया गया है, जिसका हाल ही में सीमांकन संपन्न हुआ है।आवेदनकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया है कि बीडीसी सदस्य द्वारा ग्राम सेलवाड़ा स्थित खसरा नंबर 165, जो राजस्व रिकॉर्ड में मध्यप्रदेश शासन के नाम दर्ज शासकीय भूमि बताई गई है, उससे संबंधित कथित अवैध खरीद-फरोख्त की गई है। इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की मांग की गई है।

एक साल से बंद पड़ा था वेयरहाउस, इलाके में फैली सनसनी

आगर मालवा में गेहूं की बोरियों के बीच मिली सड़ी-गली लाश, पड़ताल जारी

अगार मालवा। दोपहर मेट्रो

जिले के बड़ौद रोड़ पर लाल कोठी के सामने स्थित एक वेयरहाउस में शुक्रवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब यहां रखी गेहूं की बोरियों के बीच एक शव फंसा हुआ मिला। घटना सामने आने के बाद इलाके में लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। मृतक की पहचान अर्जुन नगर कालोनी से गुमशुदा हुए अजय उर्फ बाबू के रूप में हुई हैं। जानकारी के अनुसार, बड़ौद रोड पर स्थित एक वेयरहाउस में गत् वर्ष समर्थन मूल्य के तहत् खरीदे गए गेहूं का भंडारण किया हुआ है। पिछली 20 मई को स्प्रे करने के उपरांत वेयरहाउस बंद कर दिया गया था उसके बाद शुक्रवार को वापस स्प्रे करने के लिए कर्मचारी और हम्माल पहुंचे तो वहां तेज दुर्गंध आ रही थी। शुरुआत में उन्हें किसी जानवर के मृत होने की आशंका हुई, लेकिन जब बोरियों को हटाकर देखा गया तो सभी के होश उड़ गए। गेहूं की बोरियों के बीच एक व्यक्ति का शव फंसा हुआ दिखाई दिया। शव की स्थिति देखकर अंदेशा लगाया जा रहा है कि, वो कुछ दिनों पुराना हो सकता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए हम्मालों ने तत्काल इसकी सूचना गोदाम मालिक को दी। गोदाम संचालक ने बिना देर किए इस संबंध में पुलिस को अवगत कराया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक जांच शुरु की। पुलिस ने मौके से शव बरामद कर पंचनामा कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया।

14 साल के बालक के रूप में हुई पहचान

पुलिस की प्रारंभिक जांच में मृतक की पहचान अजय उर्फ बाबू पिता अशोक दर्जी 14 साल निवासी अर्जुन नगर कालोनी आगर के रूप में हुई है। शिनाख्त मृतक की माता एवं बुआ द्वारा की गई है।

परिजन ने दर्ज कराई थी गुमशुदगी

जानकारी के अनुसार, 11 मई शाम करीब 6 बजे अजय उर्फ बाबू पिता अशोक दर्जी अचानक लापता हो गया था। तलाश करने पर जब परिजन को सफलता नहीं मिली थी तो उन्होंने कोतवाली थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई गई थी। पुलिस प्रारंभिक स्तर पर आसपास के क्षेत्र, वेयरहाउस परिसर और उपलब्ध परिस्थितियों के आधार पर ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि मृतक वेयरहाउस के भीतर कैसे पहुंचा?

जांच में जुटी पुलिस

दूसरी तरफ मामले की जांच में जुटे आगर कोतवाली थाना प्रभारी शशि उपाध्याय का कहना है कि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत के कारणों और घटना की वास्तविक परिस्थितियों का खुलासा हो सकेगा। घटना के बाद क्षेत्र में तरह - तरह की चर्चाएं बनी हुई हैं। वेयरहाउस से मिले शव की शिनाख्त हो गई। सभी परिस्थितियों पर पुलिस की जांच जारी है। एफएसएल दल को सूचित किया गया है।

वन भूमि पर टोरेंट का कब्जा

हजारों पेड़ों की कटाई से ग्रामीणों में आक्रोश

अनूपपुर। दोपहर मेट्रो

जिले के ग्राम रक्शा में वन भूमि पर कथित अतिक्रमण और हजारों पेड़ों की कटाई का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आरोप है कि टोरेंट पावर लिमिटेड द्वारा बिना आवश्यक फॉरेस्ट क्लीयरेंस के वन भूमि पर पिलर और जीआई तार से बाड़ लगाकर कब्जा किया गया है। इस कार्रवाई से ग्रामीणों में भारी नाराजगी है और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। खसरा नंबर 258 की लगभग 9.9790 हेक्टेयर वन भूमि पर नियमों को दरकिनार कर कब्जा किया गया। उनका आरोप है कि भूमि समतलीकरण के दौरान हजारों हरे-भरे पेड़ों की कटाई कर पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाया गया है। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम, 1980 के तहत केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना वन भूमि का गैर-वन प्रयोजनों के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद बाड़बंदी और अन्य कार्य किए गए, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है।

शासकीय चरनोई भूमि की फर्जी रजिस्ट्री कराने वाला मुख्य आरोपी विनोद पाटीदार गिरफ्तार

धार। दोपहर मेट्रो

कुक्षी के निसरपुर ग्राम निम्बोल में शासकीय चरनोई भूमि की फर्जी दस्तावेजों के आधार पर रजिस्ट्री कराने और मकान निर्माण करने वाले मुख्य फरार आरोपी विनोद पाटीदार को कुक्षी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उक्त कार्रवाई उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर के आदेश और पुलिस अधीक्षक धार सचिन शर्मा के निर्देशन में की गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम निम्बोल निवासी आवेदक मोतीलाल पिता न्यादर पाटीदार ने ग्राम निम्बोल में शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत की थी। इस भूमि को ग्राम पंचायत निम्बोल के तत्कालीन अधिकारियों ने विनोद पिता हेमराज एवं उसकी पत्नी रंजना को फर्जी तरीके से वारिस बताकर स्वामित्व का प्रमाण पत्र जारी कर दिया था। इस प्रमाण पत्र के आधार पर आरोपी विनोद ने शासकीय भूमि की रजिस्ट्री करवाकर वहां मकान भी निर्माण कर लिया था। आवेदक मोतीलाल द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में रिट पिटीशन दायर की गई थी, जिस पर न्यायालय ने 8 अगस्त .2025 को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए थे। न्यायालय के आदेश के बाद नायब तहसीलदार कुक्षी द्वारा मामले की विस्तृत जांच की गई। जांच में उक्त भूमि पूरी तरह से शासकीय और चरनोई पाई गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर, तत्कालीन पंचायत सचिव साधुराम फुलमाली और तत्कालीन सरपंच केशरबाई पति मनोहरलाल पटेल द्वारा आरोपी विनोद और उसकी पत्नी रंजना पाटीदार के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार करने की पुष्टि हुई। इस पर पुलिस थाना कुक्षी में चारों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया था। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए निसरपुर चौकी प्रभारी उनि रवि वास्के के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। टीम ने तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर की सटीक सूचना के आधार पर फरार मुख्य आरोपी विनोद पिता हेमराज पाटीदार को उसके निवास ग्राम निम्बोल से ही घेराबंदी कर हिरासत में ले लिया। पुलिस अभिरक्षा में पूछताछ के दौरान आरोपी विनोद ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि सड़क किनारे स्थित इस शासकीय चरनोई भूमि पर वे पहले घूरा डालते थे।

बाद में उसने तत्कालीन सचिव के साथ मिलकर कूटरचित तरीके से इसे अपनी पत्नी के नाम करवाकर रजिस्ट्री करा ली थी। जुर्म स्वीकार करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। मामले के अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

मेट्रो एंकर मां जगदंबा महायज्ञ का शुभारंभ, कलश यात्रा में उमड़ा आस्था का जनसैलाब

जैतपुर में दिखा धर्म, संस्कृति और श्रद्धा का अद्भुत संगम

जैतपुर। दोपहर मेट्रो

धर्मनगरी ग्राम जैतपुर में आयोजित मां जगदंबा स्थापना एवं प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ का शुभारंभ प्रथम दिवस पर भव्य एवं ऐतिहासिक कलश यात्रा के साथ हुआ। पावन बाबा विश्वनाथ धाम से वैदिक मंत्रोच्चार, शंखध्वनि एवं माँ जगदंबा के जयकारों के मध्य कलश यात्रा प्रारंभ हुई। सैकड़ों श्रद्धालु मातृशक्ति ने सिर पर कलश धारण कर तथा भक्तों ने ध्वज-पताकाओं के साथ पूरे उत्साह एवं श्रद्धा से यात्रा में सहभागिता की। कलश यात्रा ग्राम जैतपुर के प्रमुख मार्गों से होती हुई भक्तिमय वातावरण के बीच महामाई माता यज्ञशाला पहुँची। मार्ग में जगह-जगह श्रद्धालुओं ने पुष्पवर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। प्रथम दिवस पर पूरे ग्राम में धर्म, भक्ति और सनातन संस्कृति की अनुपम छटा देखने को मिली। जय माँ जगदंबा के जयघोषों से सम्पूर्ण क्षेत्र गुंजायमान रहा। यज्ञशाला पहुँचने पर वैदिक आचार्यों द्वारा विधिवत पूजन-अर्चन एवं धार्मिक अनुष्ठानों का शुभारंभ कराया गया।

ग्रामीणों एवं श्रद्धालुओं की अभूतपूर्व उपस्थिति ने इस आयोजन को ऐतिहासिक बना दिया। माँ जगदंबा की असीम कृपा प्राप्ति हेतु आयोजित इस महायज्ञ के आगामी कार्यक्रमों में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालू शामिल होंगे एवं धर्म, संस्कृति और श्रद्धा का अद्भुत संगम बना ग्राम जैतपुर।

संचालनालय, महिला एवं बाल विकास

विजयाराजे वात्सल्य भवन, प्लाट नं. 29 ए अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश

क्रमांक / म.बा.वि./स्था../2026/2403 भोपाल, दिनांक 19/06/2026

// कैवियट सूचना//

म.प्र. शासन महिला एवं बाल विकास विभाग के आदेश क्रमांक 1/1021/2026- Sec-150 (WCD), 1060/E1342225/2026/50-1, 1/1/41/0001, 1/1/41/0002, 1/1/41/0003, 1062, 1048, 1050,1056,1054,1052, 1080, 1084,1082,1086 दिनांक 16.06.2026 द्वारा राजपत्रित एवं अराजपत्रित अधिकारियों/ कर्मचारियों के स्थांनातरण किये गए है। यह संभावना है कि किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा उक्त आदेशों पर स्थगन लेने के लिए माननीय उच्च न्यायालय, मुख्य खंडपीठ जबलपुर / खंडपीठ इंदौर / खंडपीठ ग्वालियर में रिट याचिका दायर की जा सकती है।

अतः यह सभी को सूचित किया जाता है कि यदि म.प्र. शासन महिला एवं बाल विकास विभाग उक्त आदेशों को चुनौती दी जाती है तो उसकी अग्रिम प्रति माननीय महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर /इंदौर / ग्वालियर को उपलब्ध कराई जाये। माननीय उच्च न्यायालय मुख्य खंडपीठ जबलपुर / खंडपीठ इंदौर/खंडपीठ ग्वालियर में संचालनालय महिला एवं बाल विकास द्वारा कैवियट दायर की जा रही है।

(हरीश कुमार खरे)
उप संचालक,
महिला एवं बाल विकास

जी-14619/26

श्रीलंका के रुमेश ने 88.68 मीटर का शानदार थ्रो कर अपने नाम किया खिताब

दोहा में नहीं चला नीरज का जादू, रहे चौथे स्थान पर, लेकिन CWG के लिए किया क्वालिफाई

दोहा, एजेंसी

नौ महीने बाद प्रतिस्पर्धी वापसी करने वाले नीरज चोपड़ा दोहा डायमंड लीग में 85.69 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ चौथे स्थान पर रहे और पदक से चूक गए। हालांकि भारतीय स्टार ने कॉमनवेल्थ गेम्स (सीडब्ल्यूजी) का क्वालिफिकेशन मार्क पार कर आगामी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए अपनी जगह लगभग पक्की कर ली, जबकि श्रीलंका के रुमेश पथिरागे 88.68 मीटर के साथ चैंपियन बने।

भारतीय स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा की नौ महीने बाद प्रतिस्पर्धी एथलेटिक्स में वापसी पदक के साथ नहीं हो सकी। दोहा डायमंड लीग के पुरुष जेवलिन थ्रो फाइनल में नीरज 85.69 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ चौथे स्थान पर रहे। वहीं, श्रीलंका के रुमेश पथिरागे ने 88.68 मीटर का शानदार थ्रो कर खिताब अपने नाम किया। ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स 86.38 मीटर के साथ दूसरे स्थान पर रहे, जबकि अमेरिका के कर्टिस थॉम्पसन ने 85.99 मीटर के थ्रो के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। नीरज पोडियम से महज 30 सेंटीमीटर दूर रह गए।

फाउल से शुरुआत, फिर दिखाई दमदार वापसी- मुकाबले की शुरुआत नीरज चोपड़ा के लिए अच्छी नहीं रही। उनका पहला प्रयास फाउल रहा, जिसके कारण वह शुरुआती रैंकिंग में काफी पीछे चले गए। हालांकि दूसरे प्रयास में उन्होंने 82.77 मीटर का थ्रो कर वापसी के संकेत दिए। इसके बाद तीसरे प्रयास में नीरज ने 85.69 मीटर का शानदार थ्रो किया और सीधे शीर्ष-3 में पहुंच गए। इस प्रदर्शन के बाद लग रहा था कि भारतीय स्टार पदक की दौड़ में मजबूती से बने रहेंगे, लेकिन आगे के राउंड में वह अपने प्रदर्शन में सुधार नहीं कर सके।

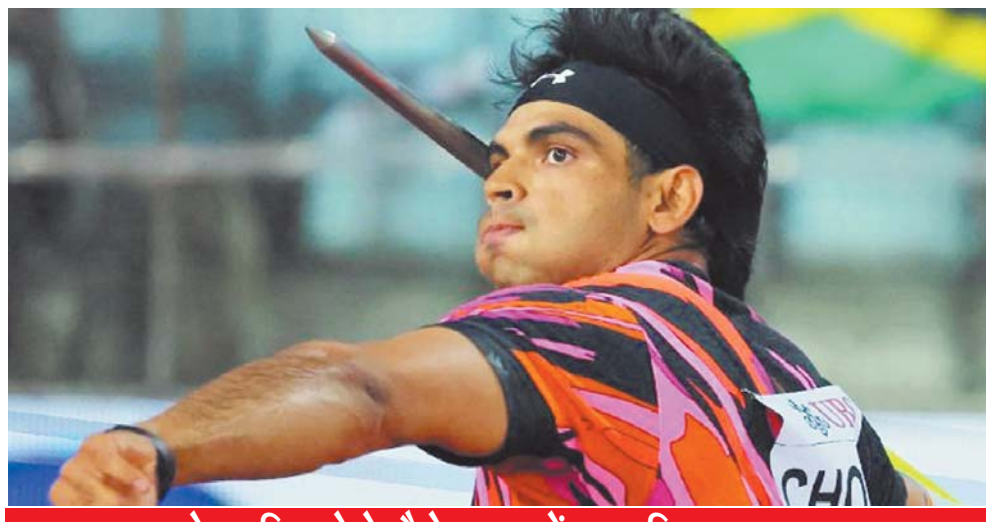

रुमेश पथिरागे ने चौथे प्रयास में पलट दिया मुकाबला

श्रीलंका के रुमेश पथिरागे ने पूरे मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने पहले दो प्रयासों में 82.62 और 84.63 मीटर का थ्रो किया, लेकिन चौथे प्रयास में 88.68 मीटर की दूरी हासिल कर मुकाबले की तस्वीर बदल दी। इसके बाद कोई भी खिलाड़ी उनके करीब नहीं पहुंच सका और उन्होंने आसानी से पहला स्थान बरकरार रखते हुए खिताब जीत लिया। पथिरागे का यह प्रदर्शन उनकी शानदार फॉर्म का एक और उदाहरण रहा।

अंतिम राउंड तक नहीं पहुंच सके नीरज

नीरज ने चौथे प्रयास में 83.45 मीटर का थ्रो किया, जबकि पांचवां प्रयास फाउल रहा। इसके चलते वह शीर्ष-तीन से बाहर हो गए। प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार, अंतिम राउंड में केवल शीर्ष तीन खिलाड़ियों को मौका मिला, इसलिए नीरज छठे प्रयास के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके। इस तरह उनका अभियान पांचवें प्रयास के बाद ही समाप्त हो गया और वह चौथे स्थान पर रहे। दोहा डायमंड लीग में नीरज पदक नहीं जीत सके, लेकिन उनके लिए एक बड़ी सकारात्मक बात भी रही। नीरज चोपड़ा ने अपने 85.69 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ कॉमनवेल्थ गेम्स (सीडब्ल्यूजी) 2026 के क्वालिफिकेशन मार्क को पार कर लिया। ऐसे में उन्होंने आगामी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए अपनी दावेदारी मजबूत कर दी है।

वापसी में दिखी उम्मीद, लेकिन पदक से चूक गए नीरज

करीब नौ महीने बाद प्रतियोगिता में लौटे नीरज चोपड़ा का प्रदर्शन मिला-जुला रहा। उन्होंने बीच मुकाबले में शानदार वापसी की और 85 मीटर से अधिक का थ्रो भी किया, लेकिन निरंतरता की कमी और फाउल प्रयासों के कारण वह पोडियम तक नहीं पहुंच सके।

फीफा विश्व कप 2026

अमेरिका के आगे बेबस दिखा ऑस्ट्रेलिया, 2-0 की जीत के साथ राउंड-ऑफ-32 में पहुंचा

सिएटल , एजेंसी

फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप-डी मुकाबले में अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की और राउंड ऑफ 32 यानी अगले दौर में अपनी जगह पक्की कर ली। सिएटल स्टेडियम में खेले गए टूर्नामेंट के 32वें मैच में अमेरिकी टीम ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया और पहले हाफ में ही दो गोल दागकर मुकाबले पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली।

आत्मघाती गोल से मिली शुरुआती बढ़त- मैच के 11वें मिनट में अमेरिका को पहला गोल मिला। फोलारिन बालोगुन के लो क्रॉस को क्लियर करने की कोशिश में ऑस्ट्रेलिया के डिफेंडर कैमरन बर्गेस से आत्मघाती गोल हो गया। इस गोल ने अमेरिका को 1-0 की बढ़त दिला दी और ऑस्ट्रेलियाई टीम पर दबाव बढ़ गया।

एलेक्स फ्रीमैन ने दोगुनी की बढ़त- पहले हाफ के अंतिम क्षणों में अमेरिका ने अपनी बढ़त दोगुनी कर ली। 43वें मिनट में सर्जिनो डेस्ट के प्रयास के बाद मिले मौके पर एलेक्स फ्रीमैन ने बॉक्स के अंदर शानदार हेडर लगाकर गेंद को गोल में पहुंचा दिया। गोल को लेकर वीडियो रिव्यू किया गया, लेकिन रेफरी ने गोल को वैध करार दिया। इसके साथ ही अमेरिका ने हाफ-टाइम तक 2-0 की मजबूत बढ़त बना ली। दो गोल से पिछड़ने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे हाफ में वापसी की कोशिश की और कुछ अच्छे हमले भी किए, लेकिन अमेरिकी रक्षा पंक्ति के सामने उसे सफलता नहीं मिली। अमेरिका ने मैच के अंतिम समय तक बढ़त बनाए रखी और ऑस्ट्रेलिया को कोई मौका नहीं दिया।

अमेरिका ने बनाई नॉकआउट में जगह

इस जीत के साथ अमेरिका ने ग्रुप-डी में लगातार दूसरी जीत हासिल की और राउंड ऑफ 32 के लिए क्वालिफाई कर लिया। विश्व कप इतिहास में यह सिर्फ दूसरा मौका है जब अमेरिकी टीम ने अपने अभियान की शुरुआत लगातार दो जीत के साथ की है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए यह हार आगे की राह को मुश्किल बनाने वाली साबित हो सकती है।

18 साल पुराने थप्पड़कांड पर फिर छिड़ी जंग

... 'हिम्मत है तो रिंग में आओ' श्रीसंत ने हरभजन को दी चुनौती

नई दिल्ली, एजेंसी

भारतीय क्रिकेट के सबसे चर्चित विवादों में से एक %स्लैपगेट% एक बार फिर चर्चा में है। पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज एस श्रीसंत ने अपने पूर्व साथी खिलाड़ी हरभजन सिंह को खुली चुनौती देते हुए रिंग में लड़ने का न्योता दिया है। श्रीसंत का यह बयान उस समय आया है जब उन्होंने एक हालिया विज्ञापन पर नाराजगी जताई, जिसे वह 2008 के थप्पड़कांड से जोड़कर देख रहे हैं। करीब दो दशक पुराने इस विवाद को लेकर श्रीसंत ने में खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने दावा किया कि हरभजन सिंह अब भी उस घटना का इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे आर्थिक फायदा उठा रहे हैं। इसी बात से नाराज होकर उन्होंने सार्वजनिक तौर पर हरभजन को फाइट के लिए चुनौती दे डाली।

श्रीसंत ने पुराने प्रमोशनल पोस्टर का किया जिक्र

लल्लनटॉप को दिए इंटरव्यू में श्रीसंत ने हरभजन को सीधे संबोधित करते हुए कहा कि अगर उनमें हिम्मत है तो वे रिंग में उतरकर मुकाबला करें। उन्होंने एक पुराने प्रमोशनल पोस्टर का जिक्र किया, जिसमें दोनों खिलाड़ी बॉक्सिंग ग्लव्स पहनकर आमने-सामने खड़े नजर आए थे। श्रीसंत ने कहा कि तस्वीरों और एडिटिंग से अलग, वह असली मुकाबला चाहते हैं। उनका कहना था कि अगर हरभजन में साहस है तो वे आधिकारिक तौर पर मुकाबले के लिए सहमति दें और रिंग में आकर आमने-सामने लड़ें।

मेरे साथ अलग नियम क्यों? एशियन गेम्स में सेलेक्ट ना होने पर भड़कीं टेनिस स्टार मनिका

नई दिल्ली, एजेंसी

भारत की स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ने एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय टीम में जगह नहीं मिलने के बाद सेलेक्शन प्रोसेस पर गंभीर सवाल उठाए हैं। देश की टॉप महिला पैडलर ने कहा कि उन्हें टीम से बाहर किए जाने का फैसला बेहद निराशाजनक है और इस संबंध में उन्हें कोई स्पष्ट कारण भी नहीं बताया गया।

वैसे मनिका बत्रा की हालिया और ताजा आईटीटीएफ टेबल टेनिस विश्व रैंकिंग में 51वें नंबर पर हैं। 31 वर्षीय मनिका बत्रा को टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा घोषित एशियन गेम्स स्क्वॉड में शामिल नहीं किया गया। उन्हें मुख्य टीम के बजाय रिजर्व खिलाड़ियों की सूची में स्वस्तिका घोष के साथ रखा गया है।

मनिका ने अपने बयान में कहा कि उन्हें सिर्फ सेलेक्शन ना होने का दुख नहीं है, बल्कि इस बात ने ज्यादा निराश किया है कि सेलेक्शन मानदंडों की व्याख्या और उनका इस्तेमाल किस तरह किया गया। उनका दावा है कि उन्हें बाहर करने के पीछे कोई वि?शेष्ज्ञ कारण शेयर न हीं किया गया।

भारतीय स्टार ने कहा कि सेलेक्शन प्रोसेस में एकरूपता को लेकर सवाल उठते हैं। उनके मुताबिक, पिछले एशियन गेम्स सेलेक्शन साइकिल में जिन मानकों और नियमों को अपनाया गया था, इस बार उनके मामले में अलग तरीके से लागू किया गया। यदि नियम वही थे, तो फिर उनके साथ अलग व्यवहार क्यों किया गया, इसका जवाब मिलना चाहिए।

घरेलू टूर्नामेंट नहीं खेलने का पड़ा असर

मनिका बत्रा का चयन नहीं होने की मुख्य वजह घरेलू प्रतियोगिताओं में उनकी अनुपस्थिति मानी जा रही है। घरेलू इवेंट्स में हिस्सा नहीं लेने के कारण वह टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की रैंकिंग में शामिल नहीं हैं। यही कारण उनके चयन के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बना। हालांकि मनि?का का मानना है कि पूरे मामले में पारदर्शिता की कमी रही है और चयन से जुड़ी जानकारी खिलाड़ियों को स्पष्ट रूप से दी जानी चाहिए। मनिका बत्रा ने इस मुद्दे को लेकर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया और भारतीय ओलंपिक संघ से हस्तक्षेप की अपील की है।

मनोरंजन **बॉलीवुड का कोना**

अनुपम खेर का वायरल वीडियो और भारतीयों पर बनी धारणाओं पर तीखा जवाब

हर चीज़ पर सवाल, और हमारी हर खुशी पर तंज

अभिनेता अनुपम खेर का एक पुराना लेकिन फिर से वायरल हो रहा वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें वे भारतीयों को लेकर देश-विदेश में प्रचलित रूढ़ियों और गलत धारणाओं पर करारा जवाब देते नजर आते हैं। वीडियो में खेर भावनात्मक और व्यंग्यात्मक अंदाज़ में बताते हैं कि कैसे भारतीयों की उपलब्धियों और व्यवहार को अक्सर गलत नजरिए से देखा जाता है।

अनुपम खेर कहते हैं कि भारतीयों पर अक्सर सिविक सेंस की कमी का आरोप लगाया जाता है, जबकि दुनिया के कई हिस्सों में जीत के बाद हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी जैसी घटनाओं को नजरअंदाज कर दिया जाता है। वहीं, अगर कोई भारतीय अपनी खुशी जाहिर करता है—जैसे एयरपोर्ट पर डांस करना या उत्सव मनाना—तो उसे भी आलोचना का सामना करना पड़ता है।

नौकरियां छीनने का आरोप और मेहनत की अनदेखी वीडियो में खेर एक और आम धारणा पर बात करते हैं कि भारतीय विदेशों में जाकर नौकरियां छीन लेते हैं। वे कहते हैं कि सच्चाई यह है कि भारतीय छात्र और पेशेवर कड़ी मेहनत, पढ़ाई और लंबे समय तक काम करके वैश्विक मंच पर अपनी जगह बनाते हैं। इसके बावजूद उन्हें अक्सर नकारात्मक रूप में देखा जाता है।

हम हर जगह हैं, फिर भी समस्या क्यों?- अनुपम खेर यह भी कहते हैं कि भारतीय दुनिया भर में डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, टैक्सी ड्राइवर और तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में योगदान दे रहे हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति को कई बार समस्या के रूप में देखा जाता है।

शोर, संस्कृति और पहचान पर सवाल

अभिनेता के अनुसार भारतीयों को कभी बहुत शोर करने वाला कहा जाता है, तो कभी उनकी संस्कृति पर सवाल उठाए जाते हैं। वे तर्क देते हैं कि भारत एक प्राचीन सभ्यता है जिसने योग, गणित, दर्शन और वसुधैव कुटुंबकम जैसे विचार दुनिया को दिए हैं, फिर भी अक्सर उसकी सांस्कृतिक पहचान को कमतर आंका जाता है। अनुपम खेर ने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा कि यह वीडियो किसी को जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि भारतीय होने की विविधता और जटिलता को समझने के लिए है। उन्होंने कहा कि भारतीय समाज भावुक, विविध और परंपराओं से जुड़ा हुआ है, और इसी विविधता में उसकी ताकत छिपी है।

टूटा 6 साल का रिश्ता, तलाक के बाद प्यार में हसीना, करेगी दूसरी शादी?

एक्ट्रेस-बिजनेसवुमन कुशा कपिला की लाइफ एक ओपन बुक जैसी है। वो अपने फैन्स से कभी कुछ नहीं छिपाती हैं। खुशी हो या गम उन्होंने हर छोटी से छोटी चीज फैन्स के साथ शेयर की है। तलाक के बाद कुशा की लव लाइफ को लेकर भी बातें होती हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा इससे इनकार किया है। पर कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। अब एक्ट्रेस की सहेली और कॉमेडियन गुरलीन पन्नू ने हिंट दिया है कि कुशा सिंगल नहीं हैं। अंगद बेदी और नेहा धुपिया के डबल डेट शो पर गुरलीन ने अनजाने में हिंट दिया कि कुशा अब सिंगल नहीं हैं। एपिसोड के दौरान की एक टिप्पणी ने जल्दी ही फैंस का ध्यान खींचा। शो में अंगद और नेहा अकसर मस्ती और रोमांटिक बातचीत करते दिखे। उनकी केमिस्ट्री पर हल्के-फुल्के अंदाज में रिएक्ट करते हुए गुरलीन ने कहा, इस पैनल पर सिंगल पर्सन का प्रतिनिधित्व करते हुए। फिर वो थोड़ी देर रुकीं और कहा कि और उसका भी। गुरलीन ने कुशा की तरफ इशारा किया। शो पर कुशा से सिंगलहुड पर राय पूछी गई। उनसे पूछा गया, सिंगल होने का सबसे अच्छा और सबसे बुरा हिस्सा क्या है? कुशा ने अपने बोर्ड पर लिखा, सिंगल होना ज्यादा ओवररेटेड है। उन्होंने आगे लिखा, अगर मौका मिले तो किसी के साथ रहो। जब बातचीत रिश्तों की ओर बढ़ी तो कुशा ने पार्टनर को लेकर अपनी सोच बताई। उन्होंने कहा, किसी के होने से हमेशा अच्छा लगता है। बेशक ये बढ़िया है और तुम्हें खुद के लिए काफी होना चाहिए, पर तुम्हारे जीवन में किसी को होना चाहिए। वरना सब कुछ बहुत खोखला सा लगता है ना। इन बातों ने अब दर्शकों के बीच कुशा के रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर अटकलें तेज कर दी हैं और कई लोग सोच रहे हैं कि क्या कंटेंट क्रिएटर ने नजदीकी तरीके से हिंट दिया कि वो किसी रिश्ते में हैं।

मेट्रो बाजार

रिलायंस के बोर्ड ने जियो के आईपीओ को दी मंजूरी, 27 करोड़ शेयर्स का होगा फ्रेश इश्यू

नई दिल्ली । जियो प्लेटफॉर्म्स के बोर्ड ने जियो के आईपीओ (इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग) को मंजूरी दे दी है और डीआरएचपी (ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस) को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास दिन के अंत में जमा किया जाएगा। यह जानकारी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी की ओर से दी गई। रिलायंस इंडस्ट्रीज की ओर से एक्सचेंज फाइलिंग में कहा गया कि प्रस्तावित आईपीओ में 10 रुपए की फेस वैल्यू वाले 27 करोड़ शेयरों का फ्रैश इश्यू शामिल होगा। इश्यू की अंतिम कीमत सेबी के इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स (आईसीडीआर) रेगुलेशंस, 2018 के तहत बुक-बिल्डिंग प्रक्रिया से तय की जाएगी। आईपीओ का ऐलान करते हुए अंबानी ने कहा कि यह मेरे लिए, पूरी रिलयांस परिवार और हमारे लाखों शेयरधारकों के लिए भावुक पल है। उन्होंने आगे कहा कि रिलायंस और उसके शेयरहोल्डर्स के बीच का रिश्ता गर्व, भरोसे, सम्मान और साथ मिलकर आगे बढ़ने पर आधारित एक गहरा और पवित्र रिश्ता है, यह एक ऐसा कमिटमेंट है जो धीरूभाई अंबानी के लिए बहुत निजी था और मेरे लिए भी उतना ही पवित्र है। आकाश, ईशा और अनंत जियो के आईपीओ प्रोसेस को संभाल रहे हैं और भविष्य में वैल्यू बनाने के मौकों के मामले में अगली पीढ़ी का नेतृत्व करेंगे।

ऑफिस मार्केट में आरईआईटी की हिस्सेदारी बढ़कर 2030 तक 30% पहुंचने की उम्मीद

नई दिल्ली । भारत में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आरईआईटी) और इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इनविट) ने बीते छह वर्षों में तेजी से विस्तार किया है और ऑफिस आरईआईटी और इंस्ट्रियल एवं वेयरहाउसिंग इनविट की बाजार हिस्सेदारी 2030 तक क्रमशः 30 प्रतिशत और 10 प्रतिशत पहुंचने की उम्मीद है। यह जानकारी शुक्रवार को जारी रिपोर्ट में दी गई।

कोलियर्स की रिपोर्ट के अनुसार, ऑफिस मार्केट में आरईआईटी के बढ़ते ट्रेंड को अच्छी क्वालिटी वाली ग्रीन-सर्टिफाइड प्रॉपर्टीज की आगमन, किराएदारों की मजबूत मांग और निवेशकों की लगातार रुचि से सपोर्ट मिल रहा है। मार्च 2026 तक, लिस्टेड आरईआईटी और इनविट का मौजूदा पोर्टफोलियो 195 मिलियन स्क्वेयर फीट से अधिक हो गया है और लगभग 37 मिलियन स्क्वेयर फीट का नया पोर्टफोलियो पाइपलाइन में है।

मौजूदा भारतीय आरईआईटी और इनविट के ऑपरेशनल पोर्टफोलियो में ऑफिस सेगमेंट का दबदबा बना हुआ है और इसकी हिस्सेदारी लगभग 84 प्रतिशत है, वहीं रिटेल और इंडस्ट्रियल व वेयरहाउसिंग सेगमेंट भी तेजी पकड़ रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि आरईआईटी और इनविट भारत के रियल एस्टेट सेक्टर में संस्थागतकरण और लोकतंत्रीकरण को तेजी से बढ़ा रहे हैं। इसके पीछे निवेशकों की बढ़ती भागीदारी, अंडरलाइंग एसेट्स का मजबूत ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, एसेट अधिग्रहण और सहायक नीतियां जैसे कारण हैं। भारतीय मार्केट में अब ऑफिस पर केंद्रित पांच आरआईआईटी के साथ-साथ एक रिटेल आरईआईटी और एक इंडस्ट्रियल व वेयरहाउसिंग पर केंद्रित इनविट शामिल हैं।

7 साल बाद फिर खुला कैलाश मानसरोवर का रास्ता

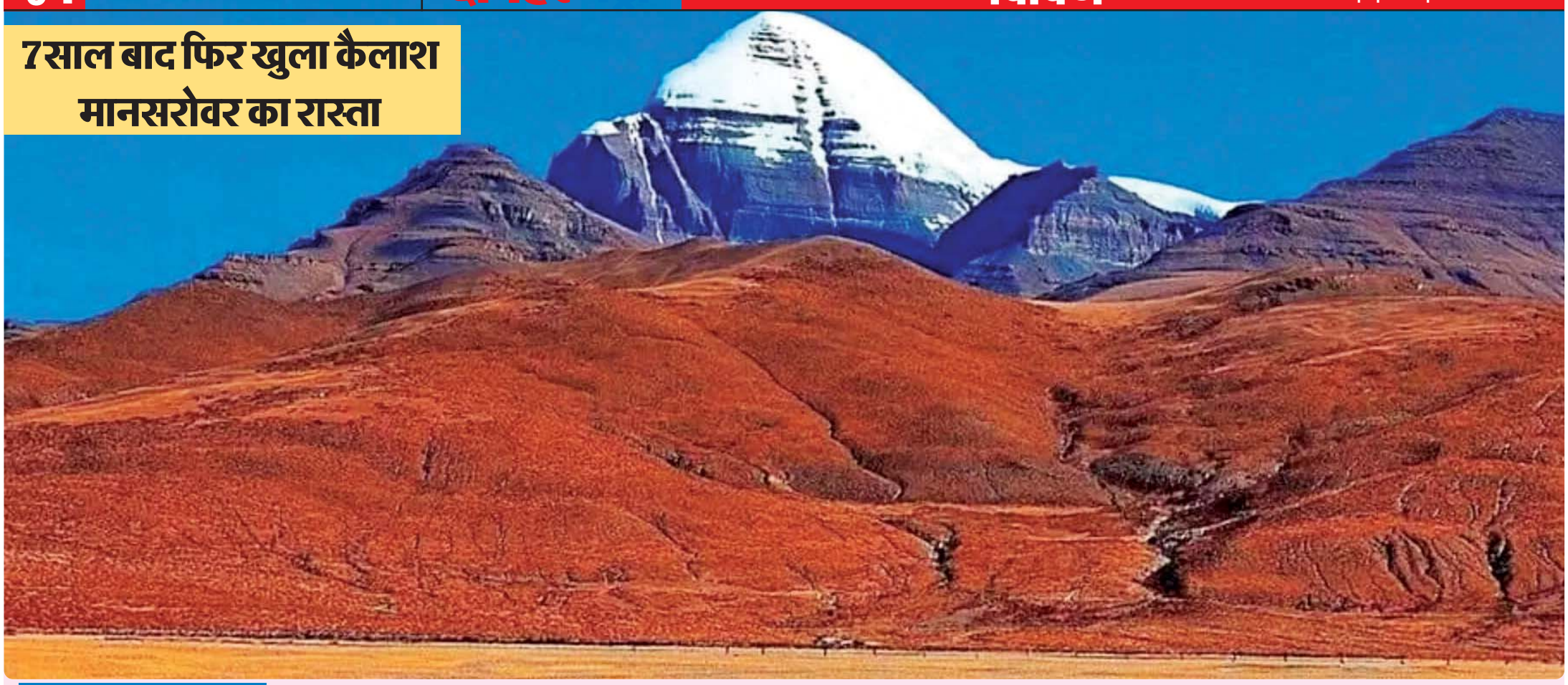

आज नाथू ला से रवाना होगा पहला जत्था

नई दिल्ली। बहुप्रतीक्षित कैलाश मानसरोवर यात्रा आज से शुरू होगी, जिसमें तीर्थयात्रियों का पहला जत्था सिक्किम में नाथू ला दर्रे से अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करेगा। भक्तों के लिए सबसे पवित्र धार्मिक यात्राओं में से एक यह यात्रा चीन के तिब्बत में स्थित पवित्र माउंट कैलाश और मानसरोवर झील की यात्रा की पुनः शुरुआत का प्रतीक है। इस वर्ष कुल 500 तीर्थयात्री नाथू ला मार्ग से यात्रा करेंगे। तीर्थयात्रियों को 50-50 प्रतिभागियों के 10 जत्थों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक जत्थे के साथ एक संपर्क अधिकारी और एक चिकित्सा सहायक होगा, ताकि यात्रा के दौरान बेहतर समन्वय और आवश्यक सहायता सुनिश्चित की जा सके।

न्यूज विंडो

लंदन में दो ट्रेनों के बीच भीषण टक्कर ड्राइवर की मौत, 80 से ज्यादा घायल

लंदन। इंग्लैंड की राजधानी लंदन में दो ट्रेनें आपस में टकरा गईं, जिससे 80 से ज्यादा यात्री घायल हो गए और ट्रेन के ड्राइवर की मौत हो गई। घायलों में 11 लोगों की हालत बेहद गंभीर है। वहीं, 22 अन्य लोगों को भी गंभीर चोटें आई हैं। हादसा लंदन के उत्तरी हिस्से में बेडफोर्ड इलाके में हुआ। हादसे के बाद इमरजेंसी सर्विस मौके पर पहुंची और घायलों को रेस्क्यू किया। एक यात्री ने बताया कि टक्कर से वह आगे की ओर उछल गया। इसके बाद उसने देखा कि साथ यात्रा कर लोगों की हड्डियां टूटी हुई थीं और वह खून से लथपथ थे। रेल ट्रैकिंग वेबसाइट के अनुसार दोनों ट्रेनें लंदन के सेंट पैनक्रास स्टेशन की तरफ दक्षिण की ओर जा रही थीं।

74 कोड़े और देश छोड़ने की मनाही मुश्किल में ईरानी सिंगर परस्तू

तेहरान। ईरान की मशहूर सिंगर परस्तू अहमदी को लेकर एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। ईरानी सिंगर को हिजाब छोड़कर स्लीवलेस ड्रेस पहनकर लाइव कॉन्सर्ट करना भारी पड़ गया है। ये मामला परस्तू के दिसंबर 2024 के एक ऑनलाइन लाइव कॉन्सर्ट से जुड़ा है, जिसमें परस्तू अहमदी ने एक स्लीवलेस ड्रेस पहनकर परफॉर्मेंस दी थी। उन्होंने इस दौरान हिजाब नहीं पहना। इस वीडियो के सामने आने के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया था, मगर बाद में छोड़ दिया गया। अब इस मामले में सिंगर को 74 कोड़ों और 2 साल तक देश न छोड़ने की सजा मिली है।

डोमिनिकन रिपब्लिक के बीचफ्रंट रिजॉर्ट में लगी आग, 1 की मौत

नई दिल्ली। कैरेबियाई देश डोमिनिकन रिपब्लिक के पर्यटन स्थल बायाहीबे स्थित एक बीचफ्रंट रिजॉर्ट में आग लग गई। हादसे में इटली की एक महिला पर्यटक की मौत हो गई, जबकि करीब 1,700 पर्यटकों और कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। मृतक की पहचान फ्रांसेस्का वैलेंटिनो के रूप में हुई है। आग विवा विंडहैम डोमिनिकस बीच होटल में लगी थी। छ्श्व॥ के मुताबिक, 3 लोगों को अस्पताल ले जाया गया, जबकि 6 अन्य का मौके पर ही इलाज किया गया। फायर ब्रिगेड ने कई घंटों के बाद आग पर काबू पा लिया।

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: कहा- फुटपाथ पर चलना मौलिक अधिकार है

'फुटपाथ पर गाड़ियों से ज्यादा पैदल चलने वालों का है हक'

नई दिल्ली, एजेंसी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फुटपाथ पर चलने का अधिकार संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि सड़कों पर मोटर गाड़ियों की आवाजाही से ज्यादा अहमियत इस अधिकार को दी जानी चाहिए। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंदुरकर की बेंच ने कहा कि पैदल चलने का अधिकार संविधान के आर्टिकल 19(1)(डी) के तहत दी गई आजादी का हिस्सा है, जो भारत के पूरे इलाके में कहीं भी आने-जाने की आजादी की रक्षा करता है। इसे आर्टिकल 19(1)(ए), 19(1)(बी), 19(1)(सी) और आर्टिकल 21 के साथ पढ़ा जाता है, जो जीवन और व्यक्तिगत आजादी के अधिकार की रक्षा करते हैं।

पैदल चलने वालों के लिए तय होना चाहिए फुटपाथ

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई सड़क है, तो यह पक्का करने की जिम्मेदारी भी होनी चाहिए कि पैदल चलने वालों के लिए एक फुटपाथ तय किया जाए और उसका रखरखाव किया जाए। यह एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसे लागू कराया जा सकता है।

यह था मामला

यह फैसला एक सड़क हादसा मुआवजा मामले से जुड़ा है जिसमें पांच साल के बच्चे की मौत हो गई थी। उसके पिता उसे स्कूल ले जा रहे थे, तभी एक टैंकर लॉरी ने बच्चे को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे उसकी कमर और शरीर का निचला हिस्सा कुचल गया। चोटों के कारण बच्चे की मौत हो गई। उस जगह पर कोई फुटपाथ या पैदल यात्रियों के लिए क्रॉसिंग नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चे के पिता को दिए जाने वाले मुआवजे की रकम बढ़ाकर 11,44,628 रुपए कर दी और निर्देश दिया कि इसका भुगतान दो महीने के भीतर किया जाए। कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें तय की गई रकम को कम कर दिया गया था।

अधिकारियों की तय होगी जिम्मेदारी

कोर्ट ने कहा कि अगर किसी नागरिक को मौलिक अधिकार मिला है, तो उसे पूरा करना प्रशासन का कर्तव्य है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कहीं सड़क मौजूद है, तो ये प्रशासन का कर्तव्य है कि वो वहां पैदल चलने वालों के लिए एक अच्छा और साफ-सुथरा फुटपाथ भी बनाकर दे। अदालत के मुताबिक, इस जिम्मेदारी को निभाने वाले 'ड्यूटी बियरर्स' में शहरी विकास प्राधिकरण, नगर निगम, नगरपालिकाएं और यहां तक कि ग्राम पंचायतें भी शामिल हैं। इन सभी संस्थाओं को अपने-अपने इलाकों में फुटपाथों का निर्माण और रखरखाव करना होगा।

रिपोर्ट : भारत में हर साल 30 हजार पैदल यात्रियों की जाती है जान

नई दिल्ली। भारत में 2019 से 2024 के बीच सड़क दुर्घटनाओं में 1.8 लाख से अधिक पैदल चलने वालों की मौत हुई है। औसतन हर साल 30,500 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस अवधि के दौरान पैदल चलने वालों की कुल मौतों में से लगभग 31% दुर्घटनाएं अकेले राष्ट्रीय राजमार्गों पर हुई हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा 2024 के लिए जारी किए गए नवीनतम दुर्घटना आंकड़ों से पता चलता है कि पैदल चलने वालों की लगभग 54% मौतें दोपहिया वाहनों और कारों की टक्कर के कारण हुईं। देश में तमिलनाडु में सबसे अधिक मौते हुई हैं।

हरियाणा : गोली लगने से एसआई घायल

दुजाना गांव के चर्चित विजय हत्याकांड का मुख्य आरोपी एनकाउंटर में ढेर

झज्जर, एजेंसी

झज्जर जिले के करोधा गांव के पास शुक्रवार देर रात पुलिस के साथ हुई गोलीबारी में एक हत्या का आरोपी मारा गया। ऑपरेशन के दौरान हरियाणा पुलिस के एक सब-इंस्पेक्टर के हाथ में भी गोली लगी। मरने वाले की पहचान बिरधाना गांव के रहने वाले संजय के तौर पर हुई है, जो दुजाना गांव के विजय सैनी की हत्या के मामले में वॉन्टेड था। पुलिस को सूचना मिली थी कि संजय किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में है। इसके बाद पुलिस टीम ने गांव कडोधा के पास रणखंडा रोड पर घेराबंदी की, जहां बदमाश और पुलिस के बीच आमना-सामना हो गया। बताया गया है कि पुलिस को देखते ही संजय ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल बदमाश संजय को तुरंत नागरिक अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

संजय।

ओडिशा : 16 लोग गिरफ्तार

बच्चा चोर समझकर भीड़ ने एनजीओ कर्मियों को पीटा, युवती के कपड़े फाड़े

रायगड़ा। जिले में मॉब लिंचिंग जैसी एक गंभीर घटना सामने आई है, जहां एक महिला और एक पुरुष एनजीओ कर्मी को बच्चा चोर होने के शक में ग्रामीणों की भीड़ ने बेरहमी से पीट दिया। यह घटना 16 जून को रायगड़ा जिले के कल्याणसिंहपुर ब्लॉक के इंटालीगुड़ा गांव में हुई। पीड़ित युवक और युवती कंधमाल जिले में एक एनजीओ के साथ काम करते हैं। दोनों कालाहांडी जिले के थुआमूल रामपुर जा रहे थे, लेकिन बताया जा रहा है कि गूगल मैप्स के गलत रास्ता दिखाने के कारण वे कल्याणसिंहपुर पहुंच गए। गांव में पहुंचने के बाद दोनों ने वहां खेल रहे बच्चों को बिस्कुट दिए। इसी दौरान कुछ ग्रामीणों को उन पर शक हुआ। चूंकि दोनों हिंदी में बात कर रहे थे और स्थानीय लोग उन्हें पहचानते नहीं थे, इसलिए अफवाह फैल गई कि वे बच्चा चोर हैं।

हिमाचल प्रदेश : करोड़पति बन गया टैक्सी ड्राइवर, तीन करोड़ की जीती लॉटरी

कांगड़ा, एजेंसी

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के एक साधारण टैक्सी चालक की जिंदगी भी एक पल में बदल गई, जब उसने 3 करोड़ रुपए की लॉटरी जीत ली। जो व्यक्ति अब तक परिवार का खर्च चलाने के लिए दिन-रात मेहनत करता था और कई बार दिहाड़ी मजदूरी करने को मजबूर हो जाता था, वह आज करोड़पति बन चुका है। फतेहपुर तहसील के रहने वाले कल्याण चंद पिछले करीब 20 वर्षों से टैक्सी चलाकर अपने परिवार का पालन-पोषण कर रहे हैं। हाल ही में वह एक सवारी को छोड़ने के लिए पंजाब के बठिंडा गए थे। काम खत्म होने के बाद उन्होंने 500-500 रुपए की दो लॉटरी टिकटें खरीद लीं। उन्हें क्या पता था कि यही दो टिकटें उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा बन जाएंगी। जानकारी के मुताबिक 13 जून को कल्याण चंद मोबाइल पर लॉटरी का लाइव ड्रॉ देख रहे थे। शुरुआत में उन्हें लगा कि इस बार भी किस्मत उनका साथ नहीं देगी, लेकिन जैसे-जैसे नंबर सामने आते गए, उनकी धड़कनें तेज होती गईं। अचानक उन्हें एहसास हुआ कि टिकट पर लिखे नंबर और ड्रॉ में निकले नंबर एक-दूसरे से मेल खा रहे हैं।

विवेक अग्रवाल बने FATF के उपाध्यक्ष

नई दिल्ली, एजेंसी

भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में वैश्विक वित्तीय अपराधों पर नजर रखने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने भारत के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए अपना उपाध्यक्ष चुना है। विवेक अग्रवाल 1 जुलाई 2026 से अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे। वह इस पद पर जाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे, जो 1 जुलाई 2025 से एफएटीएफ के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में विवेक अग्रवाल भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं। वह 1994 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और मप्र कैडर से संबंध रखते हैं। इससे पहले वह एफएटीएफ में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भी कर चुके हैं। अपनी नियुक्ति पर प्रतिक्रिया देते हुए विवेक अग्रवाल ने कहा कि यह सम्मान भारत के सामूहिक प्रयासों और मनी लॉन्ड्रिंग व आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ देश के मजबूत तंत्र की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिली मान्यता है। उन्होंने कहा कि वह इस नई जिम्मेदारी को लेकर काफी उत्साहित हैं। एफएटीएफ की प्लेनरी बैठक में सदस्य देशों ने विवेक अग्रवाल को उपाध्यक्ष चुना है। वह एफएटीएफ अध्यक्ष के साथ मिलकर संगठन के कार्यों का संचालन करेंगे और उसके उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। एफएटीएफ पेरिस में स्थित एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, जिसकी स्थापना वर्ष 1989 में जी-7 देशों द्वारा की गई थी। यह संस्था दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद की फंडिंग और अन्य वित्तीय अपराधों पर नजर रखती है।

मेट्रो एंकर | माइंस विभाग के प्रधान सचिव मुकेश मीणा ने की आधिकारिक पुष्टि

आंध्र प्रदेश के जोन्नागिरी से निकालेंगे 50 टन सोना

हैदराबाद, एजेंसी

देश के दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश से एक बेहद उत्साहजनक खबर सामने आई है, जहां के कुरनूल जिले में करीब 50 टन सोने के विशाल भंडार का पता चला है। अधिकारियों के मुताबिक, इस ऐतिहासिक खोज के बाद आंध्र प्रदेश आने वाले कुछ ही सालों में देश के भीतर सोने का सबसे बड़ा उत्पादक और सप्लायर बनकर उभर सकता है। इस भंडार से न केवल घरेलू स्तर पर सोने के उत्पादन में भारी तेजी आएगी, बल्कि विदेशों से होने वाले महंगे गोल्ड इम्पोर्ट पर भारत की निर्भरता भी काफी हद तक कम होने की उम्मीद है।

आंध्र प्रदेश के माइंस विभाग के प्रधान सचिव मुकेश कुमार मीणा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बड़ी कामयाबी की आधिकारिक पुष्टि की। उन्होंने बताया कि विभाग ने केवल जोन्नागिरी ही नहीं, बल्कि राज्य में सोने के खनन के लिए चार और संभावित स्थलों को चिन्हित किया है। इन जगहों में रामागिरी, जव्वकुला और चिगुरुकुंटा बिस्नाटम जैसी साइट्स शामिल हैं। हालांकि, इन सभी में जोन्नागिरी सबसे प्रमुख है, जहां अकेले ही 50 टन सोना मौजूद होने का मजबूत अनुमान जताया गया है।

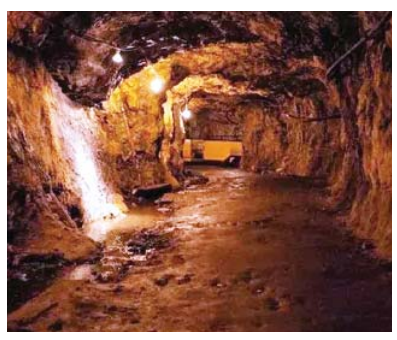

जोन्नागिरी के खजाने का गणित

इस खजाने के कमर्शियल प्रोडक्शन की तैयारियों पर बात करते हुए अधिकारियों ने बताया कि कुरनूल के जोन्नागिरी गांव में लगभग एक दशक पहले ही सोने के खनन के लिए 1,500 एकड़ जमीन आवंटित की गई थी। हालांकि, शुरुआती दौर में केवल 500 एकड़ क्षेत्र में ही खोज कार्य किया जा सका था, जहां लगभग 13 टन सोना मिलने की संभावना जताई गई थी। अब बची हुई 1,000 एकड़ जमीन पर भी जल्द ही नए सिरे से खोज का काम शुरू किया जाएगा। इस पूरे बेल्ट को मिलाकर कुल रिजर्व 50 टन के पार जाने की उम्मीद है। इस पूरी महत्वाकांक्षी परियोजना को गति देने के लिए मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू इसी महीने के अंत में आधिकारिक रूप से जोन्नागिरी गोल्ड माइनिंग के काम की शुरुआत करेंगे।

9 हजार करोड़ आंकी गई इस सोने की कीमत

भारतीय बाजार के मौजूदा समीकरणों के लिहाज से देखें तो जोन्नागिरी में मिले इस 50 टन सोने के भंडार की अनुमानित कीमत करीब 7,500 करोड़ रुपए से लेकर 9,000 करोड़ रुपए के बीच आंकी जा रही है। चूंकि सराफा बाजार में सोने के भाव रोजाना अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के हिसाब से बदलते रहते हैं। बहरहाल, इतनी बड़ी मात्रा में सोने की उपलब्धता देश की अर्थव्यवस्था और स्थानीय रोजगार के परिदृश्य को बदलने की ताकत रखती है।

उत्तराखंड में बुलडोजर कार्रवाई

धामी सरकार ने सिखों के तीर्थ स्थल के पास बनी मजार ढहाई

नानकमत्ता. एजेंसी

नानकसागर बांध क्षेत्र में सरकारी भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बांध के भीतर निर्मित अवैध मजार एवं भवन को ध्वस्त कर दिया। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान में उत्तराखंड प्रशासन एवं पुलिस विभाग ने भी सहयोग किया। बुधवार सुबह से शुरू हुई कार्रवाई के दौरान बांध क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए थे। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। अधिकारियों की मौजूदगी में जेसीबी मशीनों की मदद से अवैध निर्माण को हटाया गया। अधिकारियों के अनुसार नानकसागर बांध क्षेत्र उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की संपत्ति है। विभागीय अभिलेखों में दर्ज भूमि पर बिना अनुमति अवैध रूप से मजार एवं भवन का निर्माण किया गया था। मामले की जांच और आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अमल में लाई गई।

स्वामी,मुद्रक,प्रकाशक **राजेश सिरोठिया** द्वारा पी जी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड,करोंद-भानपुर बाइपास विलेज रासलाखेड़ी भोपाल से मुद्रित तथा ए-182 मनीषा मार्केट शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। **संपादक राजेश सिरोठिया**
स्थानीय संपादक अनिल शर्मा* आर एन आई पंजीयन क्रमांक एमपी एचआईएन/2016/68849 (*पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार) **फोन :** 0755-7963564